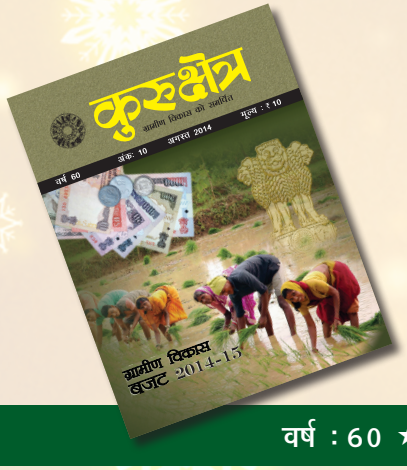

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 60 ★ मासिक अंक : 10 ★ पृष्ठ : 48 ★ श्रावण–भाद्रपद 1936★ अगस्त 2014

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 011–26100207, फैक्स : 26100207
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
संजीव कुमार साणू

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

आम बजट में रखा सभी वर्गों का ध्यान — सुनील कुमार सिंह — 3

बजट में खेती- किसानी को मिला खास तवज्जो — मनोज श्रीवास्तव — 9

सामाजिक समावेशी विकास की दिशा में आम बजट — गौरव कुमार — 13

बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा संपन्न बनाने का प्रयास — इंद्रेश चौहान — 17

शिक्षा के साथ सामाजिक विकास पर जोर — संगीता यादव — 21

रेल बजट में यात्री सुविधाओं के साथ विकासात्मक पहलुओं पर जोर — नवनीत रंजन — 27

आलू की उन्नतशील खेती — डॉ. वीरेन्द्र कुमार — 33

सेहत से भरपूर है बैंगन — साधना यादव — 39

बदल रहीं हैं रूढ़िवादी प्रथाओं को स्वयंसहायता समूहों की महिलाएं — रामचरण धाकड़ — 45

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

केंद्रीय बजट 2014 –15 में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो इशारा करते हैं कि हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उसी से बदलाव की शुरुआत करेंगे। जिस गति से हमारे संसाधनों का विकास होगा उसी गति से विकासशील भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर होता नजर आएगा।

बजट में ग्रामीण इलाकों को सुविधासम्पन्न बनाने के साथ–साथ शिक्षा और सामाजिक विकास पर भी पर्याप्त जोर दिया गया है। बजट में कृषि क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसानों को सात फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। साथ ही किसान विकास पत्र फिर से शुरू किया जाएगा। किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए 8 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार किसानों को 100 करोड़ रुपये के व्यय के साथ हेल्थ कार्ड बांटे जाएंगे। कृषि क्षेत्र में आढ़तियों की जमाखोरी से निपटने के लिए कस्बों और शहरों में किसान बाजार बनेंगे।

किसानों के सशक्तिकरण और उन्हें जागरुकता और ज्ञान प्रदान करने के लिए एक टी.वी. चैनल भी शुरू किया जाएगा।

सुनिश्चित सिंचाई हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये दिया गया है। कृषि क्षेत्र में सरकार ने चार प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया है जिसके लिए तकनीक, निजी क्षेत्र के निवेश और मार्केटिंग के नए तरीकों पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, दूसरी हरित क्रांति में प्रोटीन क्रांति पर जोर होगा।

ग्रामीण सड़क अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। ग्रामीण रोजगार की दिशा में आजीविका के अंतर्गत महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए चार प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक से ऋण दिलाने के प्रावधान को देश के 100 अन्य जिलों तक विस्तृत किया गया।

ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए शुरू में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया जा सके। साथ ही, राष्ट्रीय आवास बैंक का आवंटन ग्रामीण आवास सहायता हेतु 8000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। देश में जल संभरण विकास को गति देने के लिए एक नया कार्यक्रम 'नीलांचल' भी शुरू किया जाएगा जिसके लिए 2142 करोड़ रुपये का आरम्भिक बजट रखा गया है।

मनरेगा योजना के लिए 34 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मनरेगा को खेती से जोड़ने की योजना है। बजट में सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय और पेयजल सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें सर्वशिक्षा अभियान के लिए 28,635 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 4966 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। यही नहीं बेहतर शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु 'पंडित मदनमोहन मालवीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम' के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

'सबके लिए स्वास्थ्य' प्राप्त करने के लिए निःशुल्क दवा सेवा और निःशुल्क निदान सेवा की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। अगले छह माह में देश में कुपोषण से निपटने के लिए एक मिशन के रूप में राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाएगा। पेयजल सुलभता, सहजता और स्वास्थ्य के अनुरूप निर्बाध आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 3600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य तक पहुंचने हेतु ग्रामीण आवास के लिए केंद्र सरकार ने 8000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके जरिए नेशनल हाउसिंग बैंक ग्रामीण आवास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा।

सरकार ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने हेतु हथकरघा को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत वाराणसी में हथकरघा व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित करने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने हथकरघा–हस्तकला के संरक्षण, पुनरुत्थान और प्रलेखन के लिए 30 करोड़ रुपये की लागत से नई दिल्ली में पीपीपी आधार पर हस्तकला अकादमी की स्थापना का भी प्रस्ताव किया है।

केंद्र सरकार ने बिजली सुविधा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए हर गांव को बिजली सुविधाओं से सुसज्जित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई है और इस योजना हेतु 500 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

ई–क्रांति के जरिए सरकार ने हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने की पहल की है। इसके लिए ग्रामीण ब्राडबैंड प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया है। इस बार के बजट में सौर ऊर्जा पर भी पर्याप्त जोर दिया गया है। इसके लिए एक लाख पम्पों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा चालित कृषि पम्पसेट तथा जल पम्पिंग केंद्र योजना शुरू करने की घोषणा की गई है जिसके लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। नहरों के किनारे एक मेगावाट सौर पार्कों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये अलग से रखा गया है।

केंद्र सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए फंड की व्यवस्था करके लंबे समय से चल रही मांग को पूरा कर दिया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और इससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण मुहैया कराने हेतु आठ लाख करोड़ रुपये के फंड को जारी रखने की बात कही गई है। सरकार किसान और बाजार के बीच फासले को मिटाने पर भी जोर दे रही है। इसके लिए मंडी कानूनों की खामियों में सुधार और देश भर में दो हजार उत्पादक संगठनों को खड़ा करने पर जोर दिया गया है। जैविक खेती के विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस साल सूखे का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 100 करोड रुपये का नेशनल फंड बनाया जा रहा है।

संक्षेप में, इस बार का बजट विकासोन्मुखी बजट है। और शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जिसको बजट में शामिल न किया गया हो। जैविक खेती और सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने का निर्णय एक अच्छी शुरुआत है। कुल मिलाकर इसे ''आशाओं का बजट' कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

आम बजट में रखा सभी वर्गों का ध्यान

सुनील कुमार सिंह

आम बजट 2014-15 में हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में आम जन को त्वरित लाभ के साथ ही भविष्य की सुनहरी तस्वीर बनाने की भी कोशिश की गई है। इसमें खासकर दीर्घकालीन नीति के तहत कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को वरीयता दी गई है। यह पूरी तरह से विकासोन्मुख बजट है, जिसका प्रभाव अगले पांच वर्षों में नजर आएगा। बजट में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो इशारा करते हैं कि हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उसी से बदलाव की शुरुआत करेंगे।

आम बजट 2014–15 में हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। इसमें खासकर दीर्घकालीन नीति के तहत कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को वरीयता दी गई है। विकासशील भारत की एक बड़ी समस्या संसाधनों की कमी है। केंद्र सरकार ने 17,94,892 करोड़ रुपये के बजट में इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है। इसमें महंगाई नियंत्रण के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।

बजट में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो इशारा करते हैं कि हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उसी से बदलाव की शुरुआत करेंगे। जिस गति से हमारे संसाधनों का विकास होगा, उसी गति से विकासशील भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर होता नजर आएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में इसकी संभावनाएं दिखती हैं। जहां हमारे पास संसाधनों की कमी है, वहां पीपीपी के जरिए इसे पूरा किए जाने की तैयारी है। और जहां पैसा नहीं

है, वहां एफडीआई लाने की कोशिश की गई है। इसे रक्षा के मामले में देखा जा सकता है, जिसमें 49 फीसदी एफडीआई की पेशकश की गई है, जिससे नियंत्रण भारत का ही रहेगा। इसके अलावा खर्च प्रबंधन को ज्यादा सक्षम रखने पर जोर है। सरकार की कर नीति इस मायने में बेहतर है कि जहां हमारे इनपुट की गुंजाइश है, वहां सीमा शुल्क में कमी की गई है। और जहां हमारे उत्पाद को बढ़ाया जा सकता है, वहां उत्पाद कर में कमी की गई है। बजट में कौशल विकास को बढ़ावा देने की बात की गई है। निश्चित रूप से बेरोजगारों की लंबी फौज को कौशल विकास के जरिए स्वावलंबन की राह पर अग्रसर किया जा सकेगा। भारत को स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में चार एम्स, 12 मेडिकल कालेज के साथ ही पांच आईआईएम एवं पांच आईआईटी स्थापित करने का ऐलान किया गया है।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली के बजट में कई नई योजनाओं का समावेश किया गया है। गंगा के कल्याण के लिए महत्ती योजना, गंगा घाट का विकास, हिमालय से जुड़े राज्यों के लिए हिमालयन इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय जैसे प्रस्ताव उल्लेखनीय हैं, जिनमें निवेश से दीर्घकालीन हित जुड़े हैं। गंगा की सफाई महज धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी उसका अहम योगदान रहेगा। इसी तरह सरकार वैकल्पिक स्रोतों से बिजली पैदा करने में दिलचस्पी दिखा रही है। स्मार्ट सिटी, बड़े एयरपोर्ट, ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण जैसी योजना सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा किया जाना साबित कर रहा है कि सरकार दीर्घकालीन विकास की रणनीति को वरीयता दे रही है।

क्या हुआ सस्ता

मोबाइल, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर पार्ट, सामान्य टेलीविजन, 19 इंच से छोटे एलसीडी/एलईडी टीवी, सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण, पैकेज्ड फूड, 1000 रुपये तक के जूते, खाद्य तेल, स्टील का सामान, हीरा, कीमती पत्थर, आरओ बेस्ड वाटर प्यूरिफायर, एलईडी लाइट, लैंप, ई–बुक रीडर्स, एचआईवी–एड्स से संबंधित दवा और डायग्नोस्टिक किट, ब्रांडेड पेट्रोल, माचिस, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी, डीडीटी कीटनाशक आदि।

क्या हुआ महंगा

कोल्डड्रिंक्स, बोतलबंद जूस, रेडियो टैक्सी, सिगरेट, सिगार, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू से जुड़े उत्पाद, रेडीमेड कपड़े, कास्मेटिक, विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान, पोर्टेबल एक्स–रे मशीन, हॉफ कट डायमंड आदि।

बजट में सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था में सुधार का खाका भी दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के पहले आम बजट को मरणासन्न अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी करार दिया है। कहा कि यह बजट जन–भागीदारी और जनशक्ति को बढ़ावा देगा। यह बजट भारत को आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ कुशल और डिजिटल बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि विकास को समावेशक, सर्वदेशक और सर्वस्पर्शी होना चाहिए और इसे देश के उन क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए जो अभी तक अविकसित हैं। निश्चित रूप से इसकी प्रतिबद्धता बजट में साफ दिखती है। प्रमाण के रूप में देखें तो वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने के कई अहम कदम उठाए। सीमा शुल्क सहित दूसरे करों में कटौती करने से कॉस्मेटिक, साबुन, फुटवियर, रंगीन टीवी, भारत में बने लैपटॉप और पीसी सहित रेडियो कैब सेवा सस्ती हो जाएंगी। हालांकि सिगरेट, कोल्डड्रिंक पर टैक्स बढ़ने से ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी।

आम बजट में फैटी एसिड, कच्चे पॉम स्टेरिन आदि पर बेसिक कस्टम डयूटी घटाकर जीरो फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी

कर दी है। इस कदम से कॉस्मेटिक, साबुन और कुछ दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। इसी तरह भारत में असेंबल हुए और मैन्युफैक्चर हुए कंप्यूटर और लैपटॉप पर लगने वाली 4 फीसदी स्पेशल एडिशनल डयूटी को हटा दिया गया है। इससे कंप्यूटर और लैपटॉप सस्ते हो जाएंगे। देश में एलसीडी और एलईडी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 19 इंच से कम आकार वाले एलसीडी और एलईडी पर लगने वाले सीमा शुल्क को 19 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। रंगीन टीवी में इस्तेमाल होने वाले सीआरटी पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है जिससे वह अब सस्ता हो जाएगा। इतना ही नहीं पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को होम लोन के ब्याज पर 1.5 के बजाय 2 लाख रुपये की टैक्स कटौती का फायदा मिलेगा। डेवलपरों के नकदी संकट को दूर करने के लिए बजट में रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट पर टैक्स छूट का ऐलान किया है। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नियमों में छूट दी गई है। नेशनल हाउसिंग बैंक को 4 हजार रुपये करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी एनएचबी को 8 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे शहरी गरीबों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को मकानों के लिए सस्ता कर्ज मिलेगा। सीएसआर के जरिए भी सस्ते मकानों के निर्माण और झुग्गियों में सुधार कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्तमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण कदम कर के मामले में उठाया है। पिछले वर्ष से ही करदाता आयकर सीमा छूट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कर छूट का प्रावधान किए जाने से मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा लोगों को सीधे औसतन पांच हजार रुपये सालाना का फायदा मिल रहा है। बजट में आयकर छूट की सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की गई। वरिष्ठ आयकर दाताओं के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई। हालांकि आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर की मौजूदा दरें 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक 10 फीसदी, 5 लाख से 10 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 10 लाख से ऊपर के लिए 30 फीसदी हैं। सभी करदाताओं पर लागू 3 फीसदी के शिक्षा अधिकर (एजुकेशन सेस) में कोई राहत न देते हुए इसे भी जस का तस रखा गया है। इसी तरह मकान खरीदने पर होम लोन के ब्याज की अदायगी पर मिलने वाली आयकर छूट को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया है। विदेश जाने वालों को वित्तमंत्री ने कुछ ज्यादा शॉपिंग का मौका देते हुए अपने साथ 45 हजार रुपये तक का सामान लाने की छूट दी है। अब तक यह सीमा 35 हजार रुपये थी। पब्लिक प्राविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। इससे वेतनभोगी वर्ग को कर बचत में काफी राहत मिलेगी। बजट में टैक्स की अदायगी में दी गई

किसानों के लिए खास प्रावधान

- किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना।
- किसान विकास पत्र फिर शुरू।
- किसानों की सुविधा के लिए किसान टीवी चैनल शुरू किया जाएगा।
- हर किसान को मिलेगा मृदा उर्वरता कार्ड, 100 करोड़ रुपये की नई योजना।
- किसानों को कर्ज के लिए 8 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- आंध्र और राजस्थान में कृषि यूनिवर्सिटी, तेलंगाना और हरियाणा में बागवानी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये।

इस राहत से करीब दो करोड़ आयकरदाताओं को लाभ मिलेगा।

आधारभूत ढांचे का विकास

वित्तमंत्री ने आधारभूत ढांचे के विकास पर बजट में जोर दिया है। सड़क, बिजली, पानी की सुविधाओं के बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साल 2014–15 में सड़क क्षेत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 37880 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे करीब 8500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इसमें 3000 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर भारत के लिए है। चुनिंदा हाईवे को इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के रूप में विकसित किया जाएगा जिसके लिए एनएचएआई को 500 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसी तरह बिजली संकट को दूर करने के लिए कोयले की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के साथ–साथ बिजली उत्पादन, वितरण में काम करने वाली कंपनियों को 10 साल की टैक्स छूट भी दी है। इसी तरह सार्वजनिक–निजी भागीदारी के लिए एक 3पी इंडिया का मॉडल विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट में आवंटन किया गया है।

सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

इन दिनों देश के करीब–करीब हर राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिजली के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। बजट में भी इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। बजट में किए गए प्रस्ताव के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, लद्दाख में अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा कृषि पंपसेट के लिए सौर ऊर्जा स्कीम लांच की जाएगी जिसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। नहरों के किनारे एक मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क भी विकसित किए जाएंगे। चालू वित्तवर्ष में ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर प्रोजेक्ट को भी लागू करने की योजना है। ईवीए शीट और बैक शीट के निर्माण पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इसी तरह पीवी रिबन के फ्लैट कॉपर वॉयर पर भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। साथ ही सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने पर 5 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी को बरकरार रखा गया है।

भौतिक क्षेत्र में विकास

- शिक्षा–स्वास्थ्य के लिए मेगा प्लान।
- हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओड़िशा और राजस्थान में आईआईएम।
- जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में आईआईटी।
- उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक–एक एम्स की स्थापना का लक्ष्य।
- 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। निशुल्क इलाज की योजना।
- मध्य प्रदेश में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केंद्र।
- सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा के लिए 28635 करोड़ रुपये।
- माध्यमिक शिक्षा के लिए 4966 करोड़ रुपये।

गंगा जलमार्ग विकास

इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग विकसित करने के लिए जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। जलमार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर होगी जिसका इस्तेमाल वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसके लिए 4200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जोकि अगले छह साल में पूरा करने की योजना है। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने एनआरआई गंगा फंड की स्थापना की बात कही है। विदेश में बसे

भारतीयों के जरिए इस कोष में फंड इकट्ठा किया जाएगा और गंगा की विशेष परियोजनाओं पर इन्हें खर्च किया जाएगा। बजट में नदियों के घाटों के कायाकल्प का ऐलान किया गया है। केदारनाथ से लेकर हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना में गंगा के घाटों को और दिल्ली में यमुना के घाटों को संवारा जाएगा। इसके लिए सौ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

गैस पाइपलाइन

देश में पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए 15000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अभी देश में कुल 15000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है। जिसके जरिए पूरे देश में गैस ग्रिड विकसित होगी। सरकार 15000 किलोमीटर पाइपलाइन के लिए पीपीपी मॉडल को लागू करेगी। इसी तरह बजट में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्रश्ड कोल की आपूर्ति व वाशेरीज स्थापित की जाएंगी। विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विद्युत उत्पादन पर लागत भी कम होगी। साथ ही विद्युत उत्पादन भी बढ़ेगा।

शहरी विरासत संवर्धन योजना

शहरों की विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, वेल्लनकणी और अजमेर जैसे शहरों में आरंभ किया जाएगा। बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह परियोजना सरकार, शिक्षण संस्थान और स्थानीय लोगों की संयुक्त भागीदारी और किफायती प्रौद्योगिकी के जरिए कार्य करेगी। इसके अलावा अल्ट्रा मॉडर्न सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड थर्मल पॉवर तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।

60 साल से कम उम्र वालों को विभिन्न कर प्रावधानों के बाद होने वाला लाभ

सलाना आय	पहले कर	अब	फायदा
			(आंकड़े रुपये में)
5 लाख	3090	00	3090
6 लाख	13,390	00	13,390
7 लाख	23,690	8,240	15,450
8 लाख	41,200	18,540	22,660
9 लाख	61,800	36,050	25,750
10 लाख	82,400	56,650	25,750
15 लाख	2,11,150	1,75,100	36050
20 लाख	3,65,650	3,29,600	36050

खेलों को प्रोत्साहन

- जम्मू–कश्मीर में स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपये। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये।
- खेलों को प्रोत्साहन के लिए 100 करोड़ रुपये के शुरुआती आवंटन के साथ युवा नेतृत्व कार्यक्रम शुरू होगा।

3पी नामक पीपीपी योजना

केंद्रीय वित्तमंत्री ने वर्ष 2014–15 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए प्रस्ताव किया है कि 3पी नामक सार्वजनिक–निजी भागीदारी को मुख्यधारा में लाने में सहायता के लिए 500 करोड़ रुपये से एक संस्था गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए इस वर्ष 16 नई बंदरगाह परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। पहले चरण के लिए तुतीकोरिन में बाहरी बंदरगार परियोजना के विकास के लिए 11,635 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। कांडला और जेएनपीटी में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, चालू वित्तवर्ष में भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति घोषित की जाएगी। वित्तमंत्री ने इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर लंबे जलमार्ग विकास की एक परियोजना की भी घोषणा की। यह परियोजना 4,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर छह वर्ष की अवधि में पूरी की जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अथवा सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए टियर–1 और टियर–2 शहरों में नये हवाई अड्डे बनाने की योजना की भी घोषणा की गई। वित्तमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सड़कों के लिए 37,880 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की जिसमें से 3000 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर में खर्च किए जाएंगे।

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि की स्थापना

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि दी जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वास्तविकता है। इसका सामना हम सभी को मिलकर करना है। उन्होंने बताया कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो जलवायु परिवर्तन की विविधताओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मूल्य स्थायीकरण निधि की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि कृषि उत्पादों के मूल्य में परिवर्तन की समस्या को दूर किया जा सके। जिसके कारण अनिश्चितता का माहौल रहता है और किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में संचार सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग बताया। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में संचार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए 150 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। सरकार अंडमान निकोबार द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान दे रही है। पुडुचेरी में आपदा तैयारियों के लिए 188 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।

बदलाव के बाद टैक्स स्लैब

2.5 लाख रुपये तक	0 फीसदी
2.5 से 5 लाख रुपये तक	10 फीसदी
5 से 10 लाख रुपये तक	20 फीसदी
10 लाख रुपये से अधिक	30 फीसदी

कर छूट के अन्य प्रावधान

- टैक्स छूट के लिए निवेश सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये।
- पीपीएफ में निवेश सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये।
- हाउसिंग लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये।

60 से 80 साल के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न कर प्रावधानों के बाद होने वाला लाभ

सालाना आय	पहले कर	अब कर	फायदा
			(रुपये में)
5 लाख	00	00	00
6 लाख	8,240	00	8,240
7 लाख	18,540	3,090	15,450
8 लाख	36,050	13,390	22,660
9 लाख	56,650	30,900	25,750
10 लाख	77,250	51,500	25,750
15 लाख	2,06,000	1,69,950	36,050
20 लाख	3,60,500	3,24,450	36,050

कहां से आएगा रुपया

3 पैसा ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां।

9 पैसा सीमा शुल्क।

10 पैसा कर भिन्न राजस्व।

10 पैसा सेवा कर व अन्य कर।

10 पैसा केंद्रीय उत्पाद शुल्क।

13 पैसा आयकर।

21 पैसा नगर कर।

24 पैसा उधार एवं अन्य देयता।

रुपया कहां जाएगा

3 पैसा राज्य एवं संघीय राज्य सरकारों की आयोजना भिन्न सहायता।

15 पैसा राज्य एवं संघीय क्षेत्रों को आयोजना सहायता।

11 पैसा केंद्रीय आयोजना।

20 पैसा ब्याज अदायगी।

10 पैसा रक्षा।

12 पैसा आर्थिक सहायता।

11 पैसा अन्य आयोजना भिन्न व्यय।

18 पैसा करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा।

मद	13–14 बजटीय अनुमान	14–15 बजदीय अनुमान
		(करोड़ रुपये में)
राजस्व प्राप्तियां	1056331	118963
पूंजी प्राप्तियां	60896	605129
कुल प्राप्तियां	166529	194892
आयोजना भिन्न व्यय	1109975	1219892
आयोजना व्यय	555322	575000
कुल व्यय	1665297	1794892
राजस्व घाटा	379838	378348
राजकोषीय घाटा	522499	531177
प्राथमिक घाटा	171814	104166

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ई–मेल : sunil.saket@gmail.com

बजट में खेती- किसानी को मिला खास तवज्जो

मनोज श्रीवास्तव

बजट में खेती को खासी प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसानों को हेल्थ कार्ड मुहैया कराने के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए फंड की व्यवस्था करके लंबे समय से चल रही मांग को पूरा कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और इससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए आठ लाख करोड़ रुपये के फंड को जारी रखने की बात की गई है। जैविक खेती के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसान और बाजार के बीच फासले को मिटाने पर भी सरकार जोर दे रही है। इसके लिए मंडी कानूनों की खामियों में सुधार और देशभर में 2 हजार उत्पादक संगठनों को खड़ा करने पर जोर दिया गया है।

देश की साठ फीसदी से ज्यादा आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। यही वजह है कि वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट में खेती को खासी प्राथमिकता दी है। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है क्योंकि विभिन्न इलाकों में 60 फीसदी कृषि क्षेत्र सिंचाई सुविधा से वंचित है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हजारों एकड़ फसलें सूख जाती हैं। सिंचाई सुविधाओं का अभाव एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वित्तमंत्री ने लोकसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि किसानों के जोखिम को खत्म करने के लिए निश्चित सिंचाई की जरूरत है, क्योंकि कृषि भूमि वर्षा तथा मानसून पर आधारित है। इस योजना से सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

बजट में किए गए प्रावधानों से काफी हद तक इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। वित्तमंत्री ने खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाकर महंगाई पर काबू पाने के लिए आम बजट में खेतीबाड़ी को खास तरजीह दी है। अनाज की उत्पादकता न बढ़ने से कृषि विकास स्थिर हो गया है, जिसे गति देने के लिए वित्तमंत्री ने खेती के साथ किसानों को बागवानी, पशुधन आदि से जोड़ने का प्रयास किया है। इसके लिए खासा वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

भारत में कृषि योग्य भूमि के अलावा काफी संख्या में भूमि परती पड़ी हुई है। इस भूमि को संरक्षित किए जाने की जरूरत है। आंकड़ों पर गौर करें तो

विश्व की कुल भूमि का 2.5 प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है। दुनिया की 17 प्रतिशत जनसंख्या का भार भारत वहन कर रहा है। देश की जनसंख्या सन् 2050 तक करीब एक अरब 61 करोड़ 38 लाख से ज्यादा होने की संभावना है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के लिए अतिरिक्त भूमि कृषि के अंतर्गत लाए जाने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार के लिए सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस जरूरत को बजट में ध्यान में रखा गया है। बजट में शामिल कौशल विकास कार्यक्रम में गांवों के उन किसानों को केंद्र में रखा गया है, जो खेती के अलावा दूसरे काम में नहीं जुड़ पाते हैं। भारत की स्थिति देखें तो कृषि क्षेत्र 58.2 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। भारत के निर्यात क्षेत्र में कृषि का हिस्सा 2011–12 के 12.81 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 13.08 प्रतिशत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी वर्ष 2012 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के कृषि खाद्य उत्पाद निर्यात में भारत का हिस्सा 2.1 प्रतिशत है।

इतना ही नहीं भारत दूध, दलहन, पशुधन, पटसन, पटसन जैसा रेशा, चाय और फूलगोभी का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ ही गेहूं,चावल, फल, गन्ना, मूंगफली और तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार खेती की अनदेखी नहीं कर सकती है। यही वजह है कि वित्तमंत्री ने बजट में 500 करोड़ रुपये के मूल्य स्थिरीकरण कोष के गठन की बात भी की है। दरअसल सरकार की मंशा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को आहिस्ता–आहिस्ता खत्म करते हुए एक नेशनल मार्केट का विकास करने की है, जिससे निजी क्षेत्र और किसान बाजारों को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि एमएसपी को महंगाई की एक बड़ी वजह माना जाता है। इसी तरह किसानों को हेल्थ कार्ड मुहैया कराने के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए फंड की घोषणा की है। विभिन्न सियासी एवं सामाजिक दलों की ओर से लंबे समय से भूमिहीन किसानों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की जाती रही है। केंद्र सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए फंड की व्यवस्था करके लंबे समय से चल रही मांग को पूरा कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और इससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए आठ लाख करोड़ रुपये के फंड को जारी रखने की बात की गई है। बजट में दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दो हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी के गठन की बात की गई है। भंडारण के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपये के वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल निजी क्षेत्र को भंडारण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की ओर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पूर्वोत्तर राज्यों को जैविक खेती का केंद्र बनाने की बात की जाती रही है। बजट में इसे भी तवज्जो दिया गया है। यही वजह है कि जैविक खेती के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसान और बाजार के बीच फासले को मिटाने पर भी सरकार जोर दे रही है। इसके लिए मंडी कानूनों की खामियों में सुधार और देशभर में 2 हजार उत्पादक संगठनों को खड़ा करने पर जोर दिया गया है। बजट में कृषि के अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। इस साल सूखे का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपये का नेशनल फंड बनाया जा रहा है। उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने मृदा–स्वास्थ्य कार्ड और जागरुकता बढ़ाने के लिए किसान टीवी का वादा भी पूरा कर दिया है। भारत की खेती योग्य मिट्टी की स्थिति देखें तो हर साल करीब 2600 मिलियन टन मृदा अपरदन होता है। देश में करीब 71 लाख हेक्टेयर भूमि की मृदा ऊसर से प्रभावित है। जबकि पूरे विश्व में यह आंकड़ा लगभग 9520 हेक्टेयर के करीब बताया जाता है। जो मृदा ऊसर से प्रभावित है, उसे संसाधित करके खेती योग्य बनाए जाने की जरूरत है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार इस दिशा में कारगर साबित होगा। भूमि संसाधन विकसित करके खेती योग्य जमीन का न सिर्फ रकबा बढ़ा सकते हैं बल्कि अनाज उत्पादन का ग्राफ भी बढ़ाया जा सकता है।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष क्षरण के कारण करीब 25 लाख टन

नाइट्रोजन, 33 लाख टन फास्फेट और 25 लाख टन पोटाश की क्षति होती है। यदि इस प्रभाव को बचा लिया जाए तो हर साल करीब छह हजार मिलियन टन मिट्टी की ऊपरी परत बचेगी और इससे हर साल करीब 5.53 मिलियन टन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा भी बचेगी। अनुकूल परिस्थितियों में मिट्टी की एक इंच मोटी परत जमने में करीब आठ सौ साल लगते हैं, जबकि एक इंच मिट्टी को उड़ाने में आंधी और पानी को चंद पल लगते हैं। एक हेक्टेयर भूमि की ऊपरी परत में नाइट्रोजन की मात्रा कम होने से किसान को औसतन तीन से पांच सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मिट्टी में सल्फेट एवं क्लोराइड के धुलनशील लवणों की अधिकता के कारण मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है। कृषि में पानी के अधिक प्रयोग एवं जलजमाव के कारण मिट्टी उपजाऊ होने के बजाय लवणीय मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। वास्तव में मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को बचाना बेहद जरूरी है क्योंकि मृदा की उर्वराशक्ति के क्षीण होने का नुकसान किसी न किसी रूप में समूचे राष्ट्र को चुकाना पड़ता है। यदि फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, पोटाश सहित अन्य तत्वों को बचाकर उनका समुचित उपयोग पौधे को ताकतवर बनाने में किया जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ऐसी स्थिति में यदि किसान मिट्टी का हेल्थ कार्ड बनवाने लगेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

वित्तवर्ष 2014–15 में सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य तय किया है। किसानों को 7 फीसदी की रियायती ब्याज दर और समय से भुगतान करने पर ब्याज में 3 फीसदी छूट की योजना इस साल भी जारी रहेगी। यह 2003–04 में 86,981 करोड़ रुपये था। कृषि ऋण का 2012–13 के लिए लक्ष्य 5,75,000 करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि आलोच्य वर्ष के दौरान 6,07,375 करोड़ रुपये की उपलब्धि रही है। वर्ष 2013–14 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 7,00,000 करोड़ रुपये रखा गया है। सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मदद के लिए सरकार 5 हजार करोड़ रुपये लांग टर्म रूरल क्रेडिट फंड तैयार करेगी। आम बजट में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के लिए केंद्रीय आयोजना के तहत 11,531 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पशुओं की स्वदेशी प्रजाति के दुधारू पशुओं को विकसित करने के लिए आम बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि इस क्षेत्र में हम ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकें। पहले इस योजना के तहत गाय के संवर्धन को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें भैंस भी शामिल कर दी गई है। इसी तरह मछली पालन के क्षेत्र में विकास के लिए 'नील क्रांति' पर जोर दिया गया है। इसके लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

प्रोटीन क्रांति

कृषि क्षेत्र में अलग –अलग समय पर क्रांति का नारा बुलंद होता रहा है। कभी पीली क्रांति तो कभी नीली क्रांति पर जोर दिया गया, लेकिन अब दूसरी हरित क्रांति का फोकस प्रोटीन क्रांति पर होगा। कृषि क्षेत्र में 4 फीसदी से ऊपर की विकास दर कायम रखने के लिए तकनीक, निजी क्षेत्र के निवेश और मार्केटिंग के नए तरीकों पर जोर दिया जाएगा।

जैविक खेती को मिलेगा प्रोत्साहन

बजट में पूर्वोत्तर राज्यों में हो रही जैविक खेती को भी प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है। वैश्विक स्तर पर जैविक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के मद्देनजर पूर्वोत्तर राज्यों को जैविक खेती से व्यावसायिक फायदा मिलेगा।

अब 24 घंटे कृषि दर्शन

सरकार ने अपने पहले ही बजट में किसान टीवी चैनल शुरू करने का वादा पूरा कर दिया है। इसके जरिए बाजार भाव, खेती की नई तकनीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जल संरक्षण से जुड़ी सूचनाओं का प्रसार किया जाएगा।

राष्ट्रीय अनुकूलन निधि की स्थापना

वित्तमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जलवायु परिवर्तन से किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में सुधार किया जाना बेहद जरूरी है। साथ ही सरकार समाज के कमजोर वर्गों को उचित कीमतों पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराएगी।

कृषि के लिए नेशनल और प्राइवेट मार्केट

किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तमंत्री ने एग्री मार्केटिंग में अहम बदलाव का रोडमैप पेश किया है जिसके तहत राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार राज्यों के मंडी कानूनों में भी जरूरी सुधार कराएगी। सरकार का पूरा जोर कृषि उत्पादों के लिए प्राइवेट मार्केट यार्ड और प्राइवेट मार्केट खुलवाने पर है। साथ ही यदि आवश्यक हो तो सरकार कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए खुला बाजार बिक्री की शुरुआत करेगी।

पढ़ाई और शोध पर जोर

सरकार ने आम बजट में खेती–किसानी की पढ़ाई एवं शोध पर जोर दिया है। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे तो तेलंगाना व हरियाणा में विशेष बागवानी विश्वविद्यालय भी तैयार किए जाएंगे। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। असम और झारखंड में 100 करोड़ की लागत से दो और उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

मृदा उर्वरता कार्ड

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार प्रत्येक किसान को मृदा उर्वरता कार्ड उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। देशभर में 100 सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के इस्तेमाल में असंतुलन के बारे में चिंता बढ़ी है, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई है।

किसान टीवी चैनल

वित्तमंत्री ने आम बजट 2014–15 पेश करते हुए कहा कि किसानों की सुविधा और उनके हितों के लिए चालू वित्त वर्ष में कृषि और उससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लिए समर्पित ''किसान टीवी'' चैनल शुरू किया जाएगा। इसके जरिए किसानों को नई कृषि तकनीक, जल संरक्षण, जैविक खेती आदि से संबंधित सही एवं सटीक जानकारियां मिलेंगी। वित्त मंत्री ने इस चैनल के लिए आम बजट 2014–15 में 100 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है।

24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य

वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए गुजरात मॉडल पर कार्य शुरू कर दिया गया है। किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इस प्रस्तावित योजना के लिए 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त रखा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पहले ग्रामीण इलाके में बिजली मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद किसानों के लिए अतिरिक्त विद्युत वितरण प्रणाली लागू की जाएगी। इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है।

कृषि क्षेत्र के बजट की फैक्ट फाइल

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए – 8000 करोड़ रुपये।

कृषि सिंचाई के लिए बजट – 1000 करोड़ रुपये।

मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापना के लिए – 500 करोड़ रुपये।

कृषि टेलीविजन चैनल के लिए – 100 करोड़ रुपये।

किसानों को कर्ज देने के लिए – 8 लाख करोड़ रुपये।

पिछले वर्षों का कृषि बजट	रुपयों में
वर्ष 2009–10	411 करोड़
वर्ष 2010–11	700 करोड़
वर्ष 2011–12	1500 करोड़
वर्ष 2012–13	20208 करोड़
वर्ष 2013–14	27049 करोड़

बजट में कृषि क्षेत्र में किए गए प्रमुख प्रावधान

- राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक–एक कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित।
- हरियाणा और नवनिर्मित राज्य तेलंगाना में हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी के निर्माण का प्रस्ताव।
- देश के प्रत्येक किसान को स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा दी जाएगी।
- जलवायु परिवर्तन के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि बजट में आवंटित की गई है।
- किसानों को कर्ज देने के लिए 8 लाख करोड़ रुपये।
- 'एग्री–टेक–इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

(लेखक कृषि विभाग से जुड़े हैं)
ई–मेल : manojshriwastav1982@yahoo.in

सामाजिक समावेशी विकास की दिशा में आम बजट

देश के आर्थिक हालातों को सुधारने, आर्थिक समस्याओं को हल करने का माध्यम देश का वार्षिक बजट होता है और इस बार का बजट अपने आप में खास भी है क्योंकि अगले पांच वर्षों तक सरकार की कार्य प्रणाली का यह रोडमैप होगा। आम बजट 2014-15 को वास्तविक समावेशी विकास की दिशा में एक अहम् कदम माना जा सकता है। इस बार के बजट में जहां एक तरफ ग्रामीण विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया है वहीं दूसरी तरफ केन्द्रीय योजनाओं के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखा गया है। बजट में सामाजिक-आर्थिक और समावेशी विकास की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदमों का जिक्र इस लेख में किया गया है।

गौरव कुमार

देश में बजट सबसे गंभीर मसला होता है और यह सबसे पवित्र दस्तावेज भी है। यह सरकार के आय–व्यय का विवरण भर नहीं होता बल्कि इससे सरकार की भविष्योन्मुखी नीतियों का भी पता चलता है। एक लोककल्याणकारी राष्ट्र की सबसे प्रमुख चुनौती जनहित के उच्च आदर्शों की प्राप्ति होती है और आजादी के बाद से ही देश की लगभग सभी सरकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। इस तरह की चुनौती से इत्तर बजट अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। चूंकि यह एक बहुपक्षीय मसला होता है जोकि इसकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। बजट के कई आयाम होते हैं और इस बार भी हैं। बजट में सरकार कई पक्षों को एक साथ साधने की कोशिश करती है, कुछ पक्ष नाराज होते हैं तो कुछ पक्ष खुश होते हैं।

इसके अलावा बजट का एक भाग समानता के साथ विकास पर जोर देने से सम्बंधित भी होता है जबकि हमारा देश असमानता के कई रूपों का लगातार दर्शन करता रहा है। न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता का विस्तार दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था ऑक्सफैम की एक नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में पूंजी का अधिक हिस्सा कुछ सीमित लोगों के पास संकेंद्रित होता जा रहा है। इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। इससे समावेशी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली को नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पिछले एक दशक में अरबपतियों की संख्या 6 से बढ़कर 61 हो गई है। वर्ष 2003 में जहां संपत्तियों का संकेन्द्रण कुछ लोगों के हाथ में 1.8 प्रतिशत था वहीं यह 2008 में बढ़कर 26 प्रतिशत

तक पहुंच गया है। इस तरह की स्थिति समाज के बहुसंख्यक समूह को मुख्यधारा में आने से लगातार वंचित कर रही है।

देश के आर्थिक हालातों को सुधारने, आर्थिक समस्याओं को हल करने का माध्यम देश का वार्षिक बजट होता है और इस बार का बजट अपने आप में खास भी है क्योकि अगले पांच वर्षों तक सरकार की प्रणाली का यह रोडमैप होगा। इस बजट में यदि इस तरह के सुधारों के प्रति गंभीर ध्यान दिया गया या इसके लक्षण दिखे तो यह दीर्घकाल तक के लिए समावेशी विकास का निर्धारक बन सकता है। आम बजट 2014–15 को वास्तविक समावेशी विकास की दिशा में एक अहम् कदम माना जा सकता है। इस बार के बजट में जहां एक तरफ ग्रामीण विकास को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है वहीं दूसरी तरफ केन्द्रीय योजनाओं के प्रति भी सकारात्मक रूख प्रकट किया गया है–

ग्रामीण विकास

बजट भाषण में कृषि क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसानों को सात फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा साथ ही किसान विकास पत्र फिर से शुरू किया जाएगा। किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए 8 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार किसानों को 100 करोड़ रुपये के व्यय के साथ हेल्थ कार्ड बांटे जाएंगे। कृषि क्षेत्र में आढ़तियों की जमाखोरी से निपटने के लिए कस्बों और शहरों में किसान बाजार बनेंगे। किसानों के सशक्तीकरण और उन्हें जागरुकता और ज्ञान प्रदान करने के लिए एक टीवी चैनल भी शुरू किया जाएगा। देश में अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है। इस दिशा में सिंचाई के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। सुनिश्चित सिंचाई हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र में सरकार ने 4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बजट में कहा गया है कि प्रोटीन क्रान्ति और उच्च उत्पादकता के लिए प्रौद्योगिकी सहायता के साथ दूसरी हरित क्रान्ति कृषि क्षेत्र में अहम फोकस होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना निर्माण की दिशा में एक अहम् कदम उठाते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण–शहरी मिशन को आरम्भ करने की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फिडर सेपेरेशन के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। ग्रामीण सड़क अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। ग्रामीण रोजगार की दिशा में आजीविका के अंतर्गत महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक से ऋण दिलाने के

प्रावधान को देश के 100 अन्य जिलों तक विस्तृत किया गया। ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए शुरू में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया जा सके। राष्ट्रीय आवास बैंक का आवंटन ग्रामीण आवास सहायता हेतु 8000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया। देश में जल संभरण विकास को गति देने के लिए एक नए कार्यक्रम "नीलांचल" को 2142 करोड़ रुपये के आरंभिक परिव्यय के साथ आरम्भ किया जाएगा।

कमजोर और वंचित आबादी

अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत 50,548 करोड़ रुपये तथा जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत 32,387 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा जनजातियों के कल्याण के लिए "वन बंधु कल्याण योजना" 100 करोड़ रुपये की आरंभिक लागत से आरम्भ किए जाने की बात कही गई है। बजट में हर वर्ग और समूह के लिए विशिष्ट और हितकारी प्रावधान किए गए हैं। 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक सीमित अवधि हेतु वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की पुनर्बहाली की घोषणा

की गई है। इसके अलावा दृष्टिबाधित लोगों के कल्याणार्थ 15 नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना तथा 10 मौजूदा ब्रेल प्रेसों में आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा यूनिवर्सल डिजाईन, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर संस्थान और निःसशक्त खेलों के लिए एक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। महिला और बाल विकास के लिए किए गए प्रयासों के तहत सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा हेतु 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने की योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता और उनके सुधार के लिए जागरुकता बढ़ाने और सहायता हेतु "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। बजट में कहा गया है कि देश में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए "कला संसाधन और वस्तुओं के पारंपरिक कौशलों के उन्नयन हेतु" पुश्तैनी कला में कौशल और प्रशिक्षण के संवर्धन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु भी 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

"सबके लिए स्वास्थ्य" प्राप्त करने के लिए निःशुल्क दवा सेवा और निःशुल्क निदान सेवा की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को दूरदराज क्षेत्रों में भी सुलभ कराने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में विदर्भ और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने की घोषणा और इस मद में 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की भी घोषणा की गई है। ग्रामीण आबादी की देखभाल के लिए स्थानीय स्वास्थ्य मामलों पर शोध व अनुसंधान के लिए 15 मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की गई है। बजट में यह भी कहा गया है कि अगले छः माह में देश में कुपोषण से निपटने के लिए एक मिशन के रूप में राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाएगा। पेयजल सुलभता, सहजता और स्वास्थ्य के अनुरूप निर्बाध आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 3600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी विषैले पदार्थों, कीटनाशकों/उर्वरकों से प्रभावित 20000 बसावटों को अगले तीन वर्षों में सामुदायिक जल सुदृढ़ीकरण संयंत्रों द्वारा साफ और सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने की बात कही गई है।

शिक्षा

बजट में कहा गया है कि सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय और पेयजल सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 4966 करोड़ रुपये की राशि वित्तपोषित की गई है। स्कूलों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए बजट में कहा गया है कि 30 करोड़ रुपये की आरंभिक लागत से स्कूल आकलन कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। बेहतर शिक्षण–प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। ज्ञान बढ़ाने और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु संचार से जुड़ी प्रणाली के रूप में वास्तविक कक्षाओं की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। देश के सर्वोच्च आई. आई. टी. संस्थान के 5 नए केंद्र जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में खोलने के लिए 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा और राजस्थान में 5 नए आई आई एम खोलने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के मानदंडों को सरल किया गया है।

शहरी विकास और आवास

सरकार का अवलोकन है कि पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिये अगले 10 वर्षों में अवसंरचना और सेवाओं के नवीकरण हेतु 500 शहरी बसावटों को सहायता उपलब्ध कराई जाए। आवास की समस्या से जूझ रहे लोगों खासकर युवाओं को प्रोत्साहन हेतु गृह ऋण पर अतिरिक्त कर प्रोत्साहन की व्यवस्था। सरकार का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के सहारे निम्न लागत के सस्ते मकानों संबंधी मिशन गठित किया जाएगा। शहरी गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर समूहों, कम आय समूहों को सस्ते मकान हेतु सस्ता ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र की उधार में कमी के लिए राष्ट्रीय आवास बोर्ड से 4000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आवास बैंकों को करीब 40 अरब रुपये मिलेंगे। इसके अलावा बजट में कहा गया है कि अधिक अंशदान करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों को गंदी बस्ती विकास कार्यकलापों में शामिल किया जाएगा।

कुल मिलाकर बजट का विश्लेष्णात्मक अवलोकन एक समावेशी बजट के रूप में रेखांकित होता है। किन्तु इसके साथ ही इन सबसे अलग बजट का जो एक पक्ष भी होता है, वह है

देश की जनता के बीच का वह समूह जिनके लिए सरकार को सबसे अधिक प्रयास करने की जरुरत है। बजट आम जनता के लिए होता है और बजट का प्रमुख पक्ष जो जनकल्याणकारी होता है उसके केंद्रबिंदु गरीब और वंचित ही होते हैं। बजटीय प्रावधानों में इनके हिस्से का व्यय काफी अधिक होता है। किन्तु इतना व्यय करने के बावजूद इनकी दशा में यदि सुधार ना हो तो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसा करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण है उन लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करना। क्योंकि हमें अब तक यही पता नहीं है कि हमें सहायता किसे देनी है? वास्तव में जो कई तरह की प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है वह सब्सिडी हम किसे दे रहे हैं, हमें अक्सर इसकी प्रमाणिक जानकारी तक नहीं होती है और बजटीय आवंटन कर दिया जाता है।

प्रायः प्रत्येक सरकार गरीबी की वास्तविक गणना अपने तरीके से करती है। संभव है इसमें कई तरह की खामियां हों। क्योंकि देश में गरीबी की गणना करने का कोई सार्वभौमिक मापक विकसित नहीं किया जा सका है। कभी यह प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर किया जाता है तो कभी प्रति व्यक्ति आय पर तो कभी कैलोरी खपत के रूप में। किसे सही माना जाए और कितनी मात्रा तक इसमें संशय बरकरार है। गरीबी की गणना कई बार सरकार के प्रति जनउपेक्षा के आरोपों को बल प्रदान करती है और राष्ट्रीय स्तर पर इसे आलोचना के केंद्र में भी रखती है। पिछले वर्ष योजना आयोग का गरीबी रेखा निर्धारण के मामले में किया गया यही आकलन राष्ट्रीय आलोचना का प्रमुख विषय बना हुआ था। एक बार फिर गरीबी के आकलन का संदेहास्पद तरीका आलोचना के केंद्र में है। गौरतलब है कि पूर्व की संप्रग सरकार द्वारा सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2011–12 में देश में 36.3 करोड़ गरीब थे जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने देश में 26.9 करोड़ गरीबों के होने का दावा किया था। रंगराजन समिति के फॉर्मूला के मुताबिक वर्ष 2011–12 में देश में 29.5 प्रतिशत गरीबी थी जो कि 2009 –10 में करीब 38.2 प्रतिशत थी। इस तरह से गरीबों की संख्या दो वर्ष में घटकर 45.4 करोड़ से 36.3 करोड़ रह गई। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा वर्ष 2011–12 में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रो के लिए 1407 रुपये तय किया है। इस फॉर्मूले के आधार पर गांवों में प्रतिदिन 32 रुपये तथा शहरों में 47 रुपये खर्चने वाला गरीब नहीं माना जाएगा। सप्रंग सरकार ने गरीबी का जो आकलन किया था वह तेंदुलकर फॉर्मूला पर आधारित था। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक उपभोग व्यय 816 रुपये और शहरों में 1000 रुपये माना था यानी कि गांवों में प्रतिदिन 27 रुपये तथा शहरों में प्रतिदिन 33 रुपये खर्च करने वाला गरीब नहीं माना जाएगा। इसके अनुसार 2009–10 में गरीबी 29.8 प्रतिशत थी जोकि वर्ष 2011–12 में घट कर 21.9 प्रतिशत रह गई।

देश में गरीबों की और वास्तविक सामाजिक समावेशन के लिए एक विश्वसनीय डाटा होना आज एक गंभीर मसला हो चुका है। होना यह चाहिए कि देश में एक मजबूत और सशक्त डाटा केंद्र बनाया जाए जो अधिक वैज्ञानिक पद्धति के साथ विश्वसनीय तरीके से बनाया जाए। इसका लाभ यह होगा कि हम अनावश्यक संशय से बचेंगे, वांछित लक्ष्य समूह तक सरलता से पहुंच सकेंगे और राजकोषीय अपव्यय को रोकने में कारगर कदम उठा सकेंगे।

(लेखक पी आर एस लेजिस्लेटिव रिसर्च, नई दिल्ली में लैम्प फैलो हैं)
ई–मेलः gauravkumar1588@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।
कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
पता .....
..... पिन .....
इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा संपन्न बनाने का प्रयास

इंद्रेश चौहान

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट में ग्रामीण इलाकों का खास ख्याल रखा है। ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास के लिए न सिर्फ पूर्ववर्ती योजनाओं को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया गया है बल्कि कई नई कल्याणकारी योजनाओं के जरिए भारत के ग्रामीण इलाकों को संवारने का प्रस्ताव किया गया है।

भारत की ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। ऐसे में ग्रामीण विकास के बिना सशक्त और संपन्न भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता है। यही वजह है कि सरकार ने आम बजट में ग्रामीण भारत को खास तवज्जो दिया है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से तमाम ऐसे उपक्रम किए गए हैं, जिनके जरिए जल्द ही भारत की तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। गांवों में विकास की धुरी सड़कें होती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। गांवों में सड़कें बनने के बाद वहां विकास के तमाम संसाधन बढ़े हैं। चूंकि गांवों को सड़क से जोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई है। यही वजह है कि मौजूदा बजट में सरकार की ओर से गत वर्ष की अपेक्षा बढ़ोतरी की गई है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 14,389 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। निश्चित रूप से इस योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। जहां लोगों को पगडंडियों से आवागमन करना पड़ता था वहां अब पक्की सड़कें हैं। सड़कों के बनने के साथ ही गांवों में रोजगार के संसाधन भी बढ़े हैं। शत–प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले (पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव) सड़क–संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा कि इस योजना की कामयाबी को देखते हुए इसे और बेहतर बनाया जाएगा। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट पिछले साल 80194 करोड़ रुपये से घटाकर 7502 करोड़ रुपये कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण

विकास में योगदान देने वाली अन्य कई योजनाओं को विस्तारित किया गया है। मसलन जल संसाधन मंत्रालय का बजट 1500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3245 करोड़ रुपये कर दिया गया है। देश के 272 जिलों में लागू बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड योजना में सुधार करते हुए इसके जरिए सब–डिस्ट्रिक्ट पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस फंड का इस्तेमाल ग्रामसभाओं और पंचायतों के कामकाज व सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी होगा।

गांवों में ई–क्रांति

ई–क्रांति के जरिए सरकार ने हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने की पहल की है। इसके लिए ग्रामीण ब्राडबैंड प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया है। इसके तहत स्कूलों और गांवों में इंटरनेट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट और तकनीकी मिशन, आईटी कौशल में प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं तथा सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट उपलब्ध कराना चाहती है।

पूरा होगा छत का सपना

हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है उसके सिर पर एक छत हो। ग्रामीण इलाके में अभी भी तमाम लोग अपना आवास नहीं बना पाए हैं। ऐसे लोगों का सपना सरकार पूरा करेगी।

वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' के चुनावी वादे को निभाने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण आवास के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके जरिए नेशनल हाउसिंग बैंक ग्रामीण आवास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा।

मिलेगा शुद्ध पेयजल

अभी भी ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिल पाई है। सरकार ने दूषित जल की मार झेल रहे देश के करीब 20 हजार गांवों और बस्तियों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 3600 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसके जरिए समुदाय स्तर पर जलशोधन किया जाएगा।

सामुदायिक रेडियो

देश में और खासकर ग्रामीण भारत में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना के लिए अब तक लगभग 400 मंजूरियां दी गई हैं। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की एक नई योजना शुरू की जा रही है। यह योजना लगभग 600 नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो केंद्रों के लिए धन उपलब्ध कराएगी।

हथकरघा को प्रोत्साहन

सरकार ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में हथकरघा को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत वाराणसी में हथकरघा व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित करने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने यूपी के वाराणसी, बरेली, लखनऊ और गुजरात के सूरत, कच्छ, बिहार के भागलपुर, मैसूर व तमिलनाडु में 200 करोड़ रुपये की लागत से आठ बड़े वस्त्र उत्पादन समूह स्थापित करने की घोषणा की। वित्तमंत्री ने हथकरघा– हस्तकला के संरक्षण, पुनरुत्थान और प्रलेखन के लिए 30 करोड़ रुपये की लागत से नई दिल्ली में पीपीपी आधार पर हस्तकला अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव किया। उन्होंने पश्मीना प्रोत्साहन कार्यक्रम (पी–3) और जम्मू–कश्मीर के शिल्प विकास कार्यक्रम के लिए भी 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए।

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना

ग्रामीण भारत में बिजली एक बड़ी समस्या है। हर प्रदेश के ग्रामीण अभी भी बिजली सुविधा के लिए परेशान रहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने बिजली सुविधा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए हर गांव को बिजली सुविधाओं से सुसज्जित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई है। बजट में सरकार ने देश के सभी गांवों तक बिजली

पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। सरकार ने इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

15 मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र

भारत के ग्रामीण इलाके को स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बाद भी अभी तक ग्रामीण इलाके में वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसकी जरूरत है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी मौजूदा बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार इस बार राज्यों में 15 मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगी।

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन

केंद्र सरकार ने भारतीय गांवों में स्वयंसहायता समूह के जरिए चार फीसदी की दर से महिला ऋणों को 100 जिलों में बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत सरकार ने 100 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है। इससे योजना के तहत पहले 150 जिलों में 4 फीसदी तथा अन्य जिलों में सात फीसदी की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का उद्देश्य वहनीय आजीविका विकल्पों के जरिए ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का है। इस मिशन के तहत महिला एसएचजी को 150 जिलों में 4 प्रतिशत और अन्य सभी जिलों में 7 प्रतिशत अविलंब अदायगी पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

स्वावलंबन की राह

ग्रामीण इलाके में अभी भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार ने ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी पहल की है। ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवा स्थानीय स्तर पर ही कोई रोजगार शुरू कर सकें। सरकार ने इसे नाबार्ड के जरिए जोड़ा है।

2019 तक सभी गांवों को स्वच्छ रखने का लक्ष्य

केंद्र सरकार 2019 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर सभी गांवों को पूरी तरह स्वच्छ करने की योजना बना रही है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं रखा है, लेकिन पुरानी योजनाओं पर चलते हुए ही वह संसाधन उपलब्ध करा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी का सहयोग भी मांगा है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण–शहरी मिशन

ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजना आधारित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण–शहरी मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन में आर्थिक गतिविधियां और कौशल विकास करना भी शामिल है। इसमें विभिन्न योजना अनुदानों का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीकरण के लिए गुजरात ने सफलतापूर्वक ग्रामीण–शहरी विकास मॉडल को अपनाया है।

कृषि पंपसेट

वित्तमंत्री ने बजट में कहा कि एक लाख पम्पों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम सौर ऊर्जा चालित कृषि पम्प सेट तथा जल पम्पिंग केन्द्र योजना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं। नहरों के किनारे एक मेगावाट सौर पार्कों के विकास के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये अलग से रखा गया है। पवन ऊर्जा का त्वरित विकास करने के लिए मैं त्वरित अवमूल्यन के फायदे को पुनः बहाल करने का प्रस्ताव रखता हूं। पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा का स्थानांतरण सुसाध्य बनाने के लिए हरित ऊर्जा कोरीडोर परियोजना को इस वित्तवर्ष में त्वरित किया जाएगा।

कृषि कार्यों से जुड़ेगा मनरेगा

मनरेगा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस योजना को खेती के साथ जोड़ा जाएगा। मनरेगा की वजह से महंगाई और श्रमिकों की किल्लत बढ़ने जैसे आरोपों के बावजूद सरकार ने इसके लिए 34 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है।

सभी को बैंक सेवाएं

भारतीय रिजर्व बैंक छोटे बैंकों को लाइसेंस देने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा। ऋण वसूली के लिए छह नए न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2014–15 पेश करते हुए कहा कि देश के सभी परिवारों को बैंक की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से एक वित्तीय समावेशी मिशन शुरू किया जाएगा। इस कदम से विशेष रूप से महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और मजदूरों सहित समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर विशेष तौर पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवारों में दो बैंक खाते खोले जाने का प्रस्ताव है। वित्तमंत्री ने कहा कि बुनियादी क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में काफी बाधा है। संसाधनों के लिए बुनियादी क्षेत्र में बैंकों को प्रतिकूल संभावित आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए लोचशील ढांचे वाले दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तरदेयता के लिए बैंकों को सीआरआर, एसएलआर और प्राथमिक क्षेत्र के वित्तपोषण जैसे न्यूनतम नियामक के साथ बुनियादी क्षेत्र को अधिक मात्रा में दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।

वसूली न्यायाधिकरण स्थापना

वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक छोटे बैंकों और अन्य बैंकों को लाईसेंस देने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा। ऐसे बैंकों को छोटे व्यापारियों, असंगठित क्षेत्र, कम आय वाले परिवारों, किसानों और प्रवासी श्रमिकों आदि की जरूरत को पूरा करने के लिए ऋण देने में सक्षम बनाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बढ़ते गैर–निष्पादक संसाधनों (एनपीए) के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए वित्तमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि चंडीगढ़, बंगलुरू, एर्नाकुलम, देहरादून, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में छह नए ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।

नमामि गंगे मिशन की शुरुआत

वित्तमंत्री ने समन्वित गंगा संरक्षण मिशन (नमामि गंगे) का प्रस्ताव किया है। इस मिशन के लिए वर्तमान बजट में 2037 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है। गंगा नदी के संरक्षण की दिशा में योगदान करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय के उत्साह के उपयोग के लिए गंगा के लिए एनआरआई निधि की स्थापना की जाएगी जो विशेष परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करेगी। वित्तमंत्री ने यह भी बताया कि केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में नदियों के किनारे घाट के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है क्योंकि नदियों के किनारे और घाट न केवल हमारी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है बल्कि इनमें से अनेक पवित्र भी हैं। बजट में देशभर में नदियों को जोड़े जाने के प्रथम प्रयासों को भी शामिल किया गया है। वित्तमंत्री ने इस दिशा में गंभीर रुख अपनाते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए चालू बजट में 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

ग्रामीण भारत के लिए बजट में प्रमुख प्रावधान

- सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 14389 करोड़ रुपये का बजट दिया गया।
- देश के 20 हजार गांव और बस्तियों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 3600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- मनरेगा के लिए 34000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ग्रामीण आवास के लिए 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : indreshc22@gmail.com

शिक्षा के साथ सामाजिक विकास पर जोर

संगीता यादव

केंद्रीय बजट 2014-15 में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सरकार ने बजट में सामाजिक दायित्व का भी बखूबी निर्वहन किया है। बजट में महिलाओं, बालिकाओं को आगे बढ़ाने, उनके सर्वांगीण विकास के साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। आम बजट में सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण का भी प्रावधान किया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा भी शुरू की जाएगी। शैक्षिक विकास के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण मद में 500 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।

केंद्रीय बजट 2014–15 में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सरकार ने बजट में सामाजिक दायित्व का भी बखूबी निर्वहन किया है। अल्पसंख्यकों के लिए कई कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं। वैसे तो पूरे अल्पसंख्यक समुदाय की पढ़ाई–लिखाई में सरकार और मदद करेगी, लेकिन लड़कियों की तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी।

बजट में महिलाओं, बालिकाओं को आगे बढ़ाने, उनके सर्वांगीण विकास के साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। आम बजट में सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण का भी प्रावधान किया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा भी शुरू की जाएगी। शैक्षिक विकास के लिए शिक्षण–प्रशिक्षण मद में 500 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एम्स के लिए 500 करोड़ तो 12 नए मेडिकल कालेज भी खोलने का प्रावधान किया गया है।

शैक्षिक विकास की दिशा में बढ़े कदम

केंद्र सरकार के पहले बजट में ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए हैं। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2014–15 के आम बजट में पांच नए आईआईटी और पांच ही आईआईएम खोलने का ऐलान किया है। जम्मू–कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में पांच और आईआईटी बनाने का वादा किया है तो हिमाचल प्रदेश,

पंजाब, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र में पांच आईआईएम बनाने का भी प्रस्ताव रखकर उच्च शिक्षा का सपना देख रहे छात्रों को बड़ी सौगात दी गई है। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये की रकम अलग से रखने का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह सरकार ने उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण में भी सहूलियतें जारी की हैं। मध्य प्रदेश में हूमनिटिस के लिए जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में रखा है। माध्यमिक शिक्षा योजना के तहत 6 हजार आदर्श विद्यालयों को खोलने के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सर्वशिक्षा अभियान के लिए 28,635 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया हैं। वहीं मध्यान्ह् भोजन योजना के तहत 13,215 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 111 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ऑनलाइन कक्षाओं और पाठयक्रमों को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही वर्ष 2014–15 के आम बजट में ग्लोबल मानकों के अनुरूप टीचर स्टाफ तैयार करने के लिए पंडित एम. एम. मालवीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को 3905 करोड़ रुपये दिए गए हैं जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी आवंटन शामिल है। आईसीटी के लिए 200 करोड़ रुपये तो इंदिरा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में दूरस्थ शिक्षा के लिए 125 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

चार एम्स, 12 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे

वित्तमंत्री आम बजट में सबसे अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर मेहरबान रहे। बजट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एम्स की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही बजट में पहले से अनुमोदित 58 सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का भी प्रावधान किया है। वित्तमंत्री ने निशुल्क दवा और इलाज के लिए 'सबके लिए स्वास्थ्य' योजना प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का भी ऐलान किया। आम बजट में देशभर की 31 औषध जांच प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने और देश के सभी अस्पतालों में दंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात कही। इसके अलावा नई सरकार ने कुपोषण की बिगड़ती स्थिति को दुरुस्त करने के लिए अगले छह महीने में विस्तृत तंत्र खड़ा करने का भी ऐलान किया है। वित्तमंत्री ने टीबी उन्मूलन के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स और चेन्नई स्थित मद्रास मेडिकल कॉलेज में दो राष्ट्रीय वरिष्ठ व्यक्ति संस्थान भी स्थापित करने की घोषणा की है। दंत चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुसंधान रेफरल अस्पताल स्थापित करने का भी बजट में प्रावधान किया गया है।

'स्किल इंडिया' कार्यक्रम

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश करते हुए विविध प्रकार के कौशल सिखाने के लिए राष्ट्रीय मल्टी स्किल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इसे स्किल इंडिया के नाम से जाना जाएगा। इस कार्यक्रम से युवाओं को कुशल बनाया जाएगा और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा उद्यमिता कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए वेल्डरों, बढ़ई, राजमिस्त्री, लुहारों और बुनकरों जैसे पारंपरिक पेशे से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ब्रेललिपि चिह्नित करेंसी नोट

दृष्टिहीनों के लिए ब्रेललिपि चिन्हित करेंसी नोट मुद्रित होगा। दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल पाठ्य पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिए 15 नए ब्रेल प्रेस की स्थापना और मौजूदा दस ब्रेल प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी।

विकलांगों पर ध्यान

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार विकलांगों को सशक्त बनाने के समान अवसर मुहैया कराएगी। यूनिवर्सल इनक्लूसिव डिजाइन

और मेंटल हेल्थ रिहेब्लिटेशन के लिए राष्ट्रीय संस्थान खोलने का जिक्र किया गया है। सेंटर फॉर डिसैब्लिटी स्पोर्ट्स बनाने की घोषणा भी बजट में की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि भारत उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख देश के रूप में उभरा है लेकिन बालिकाओं के प्रति अब भी देश के कई भागों में भेदभाव किया जाता है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने का प्रस्ताव है जिससे महिलाओं के कल्याण के लिए सेवाएं सुलभ और सुगम बनाने में मदद मिलेगी और जनता को बालिकाओं के प्रति जागरूक बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिला जागरुकता अभियान

बजट में 150 करोड़ रुपये खर्च करके बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी। यह योजना गृह मंत्रालय चलाएगा। इसके साथ ही बालिकाओं और महिलाओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्त्री–पुरुष के बीच भेदभाव दूर करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय शामिल किए जाएंगे। इसी तरह निर्भया कोष का इस्तेमाल कर दिल्ली एनसीआर के सभी जिलों में स्थित सरकारी और निजी अस्पतालों में क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर खोले जाएंगे।

मासिक पेंशन योजना

बजट में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सभी सदस्यों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए वर्तमान वित्तवर्ष में 250 करोड़ रुपये का आरंभिक प्रावधान किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना की अनिवार्य वेतन सीमा को 6500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है और इसके लिए वर्तमान वित्तवर्ष में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भविष्य निधि खातों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए यूनिफोर्म एकाउंट नंबर आरंभ किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु उपाय

वित्तमंत्री ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक उपायों की घोषणा की। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुरू की थी, जिससे कुल 03 लाख 16 हजार वरिष्ठ नागरिकों ने पेंशन का लाभ उठाया। यह योजना 60 अरब 95 करोड़ की निधि के साथ शुरू की गई थी। 60 वर्ष और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 की सीमित अवधि के लिए इस योजना को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

हथकरघा व्यापार सुविधा केन्द्र और शिल्प संग्रहालय

हमारी संस्कृति और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से वाराणसी में हथकरघा व्यापार सुविधा केन्द्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। वित्तमंत्री ने वाराणसी, बरेली, लखनऊ, सूरत, कच्छ, भागलपुर, मैसूर और तमिलनाडु में 200 करोड़ रुपये की लागत से आठ बड़े वस्त्र उत्पादन समूह स्थापित करने की भी घोषणा की।

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई कार्यक्रम

केन्द्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि परंपरागत कला और शिल्प की जो समृद्ध विरासत है उसके संरक्षण और अल्पसंख्यकों के विकास हेतु परंपरागत कलाओं में कौशल और प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए ''कला, संसाधन और वस्तुओं में परंपरागत कौशल का उन्नयन'' नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्कूली शिक्षा विभाग के लिए आवंटित की गई है।

अनुसूचित जाति कल्याण योजना

वित्तमंत्री ने वर्ष 2014–15 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि उनकी सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और अनुसूचित योजना तथा टीएसपी के अधीन इस वर्ष क्रमशः 50,548 करोड़ रुपये और 32,387 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। अनुसूचित जातियों के युवा उद्यमियों के लिए ऋण बढ़ोतरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जनजातियों के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपये के आरम्भिक आवंटन के साथ 'वन बंधु कल्याण योजना' शुरू की जा रही है।

बजट में खास

- 6 हजार आदर्श विद्यालय खोलने के लिए 3905 करोड़ रुपये आम बजट में दिए गए हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मध्यान्ह् भोजन योजना के लिए 13215 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।
- 4966 करोड़ रुपये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए।
- स्कूल मूल्यांकन कार्यक्रम के लिए 30 करोड रुपये आवंटित।
- बजट में इग्नू में दूरस्थ शिक्षा के लिए 125 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- 5 नए आईआईटी और पांच नए आईआईएम खोलने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित।
- बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, हिमाचल और पंजाब में खुलेंगे नए आईआईएम।
- छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और केरल में खुलेंगे नए आईआईटी।

कोयला आधारित अत्याधुनिक ताप बिजली प्रौद्योगिकी योजना

वित्तमंत्री ने बजट भाषण आम बजट 2014–15 में ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की विभिन्न पहलों की घोषणा की है। उन्होंने स्वच्छ और ज्यादा कारगर ताप विद्युत को बढ़ावा देने के लिए "अल्ट्रा माडर्न सुपर क्रिटीकल कोल आधारित ताप विद्युत प्रौद्योगिकी" के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक प्रबंध करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोयला लिंकेज की यौगिकीकरण की प्रक्रिया कोयला परिवहन को अधिकतम करेगी और इस प्रकार विद्युत की लागत कम होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू व कश्मीर के लद्दाख में अल्ट्रा गंगा सौर विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किए गए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की मंशा है कि कोयला क्षेत्र में आरक्षित मिथेन का उत्पादन और दोहन त्वरित गति से किया जाएगा। ऐसे स्थलों से अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए पुराने या बंद पड़े कुओं को दोबारा खोलने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना की भी तलाश की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की उपयोगिता मिशन मोड में तेजी से बढ़ायी जाएगी क्योंकि यह स्वच्छ है और इसकी प्रदायगी में सहूलियत होती है।

पर्यटन क्षेत्र विकास

वित्तमंत्री ने वर्ष 2014–15 के आम बजट में पांच पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया है जो विशेष विषय पर आधारित होंगे। वर्तमान वित्तवर्ष के लिए इन पर्यटन क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत पर्यटन के विकास और उद्योग के रूप में रोजगार सृजन के लिए बाहरी

संभावनाएं उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि दुनियाभर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सारनाथ–गया–वाराणसी बौद्ध गलियारा विकसित किया जाएगा। इस मार्ग पर विश्व–स्तरीय पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वित्तमंत्री ने इन शहरों की विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय विरासत शहरी विकास एवं संवर्धन योजना की शुरुआत की भी घोषणा की। यह कार्यक्रम मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, वेल्लनकणी और अजमेर जैसे शहरों में आरंभ किया जाएगा। वर्तमान बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह परियोजना सरकार, शिक्षण संस्थान और स्थानीय समुदाय की संयुक्त भागीदारी और किफायती प्रौद्योगिकी के जरिए कार्य करेगी। चालू वित्तवर्ष से राष्ट्रीय धार्मिक जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए इस वित्तवर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने पुरातत्व स्थलों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था की है।

रक्षा क्षेत्र में उड़ान

वित्तमंत्री ने देश के विकास के साथ ही रक्षा क्षेत्र का भी खासा ध्यान रखा है। रक्षा बजट को जहां पिछले साल की तुलना में 12.5 फीसदी बढ़ाकर 2.29 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, वहीं इस क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश (एफडीआई) के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। पहले 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई थी। सरकार को उम्मीद है कि एफडीआई के इस फैसले से रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ेगा। साथ ही सेना के आधुनिकीकरण में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर देश की सुरक्षा को मजबूत करने का अच्छा प्रयास किया है। रक्षा की नई योजनाओं की घोषणा करते हुए वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) के जरिए होगा और इसका प्रबंधन भारतीय कंपनियों के हाथ में ही होगा। जेटली ने अपने बजट में सेवानिवृत्त सैनिकों और अधिकारियों के वन रैंक वन पेंशन की योजना को मंजूरी देते हुए इस मद में 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। वित्तमंत्री ने रक्षा के आधारभूत संसाधनों और निर्माणों को मजबूत करने के मकसद से 5000 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का अलग से इंतजाम किया है। इसमें से 100 करोड़ रुपये सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल व्यवस्था को मजबूत करने में खर्च होंगे।

पहली बार किया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रावधान

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये का पहली बार प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में बनेगा। आम बजट के तहत एक राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का भी निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 50 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन का प्रस्ताव है। चीन और पाकिस्तान की ओर से आए दिन घुसपैठ की घटनाओं के मद्देनजर आम बजट में सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत विकास की योजना का खाका तैयार किया गया है। इसी के तहत सीमाओं पर चौकियों को मजबूत व आधुनिक बनाने के लिए 2250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है। कानून व्यवस्था के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम रोल के लिए राज्य के पुलिस तंत्र को मजबूत किया जाएगा। पुलिस बेड़े की मजबूती के लिए 3000 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए इस बजट में 59,450 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

CL हॉल ऑफ फेम

सिविल सेवा '13 की प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ -241 (समान्य श्रेणी) है
आप 241 में से 180 अंक GS II (CSAT) में ही प्राप्त कर सकते हैं
बहुत से CL विद्यार्थियों ने यही किया है

CL पंजीकरण संख्या	विद्यार्थी का नाम	यूपीएससी अनुक्रमांक	CSAT प्राप्तांक	CSAT प्रतिशत (200 में)	सिविल सेवा (प्रा.) 2013 के कट ऑफ (241) में CSAT के प्राप्तांक का प्रतिशत
1988094	अभिषेक आनंद	225650	194.18	97.1	80.6
2699229	राज कमल रंजन	220538	190.83	95.4	79.2
5619304	श्रुजीत वेलुमुला	044017	190	95.0	78.8
5619556	शेख रहमान	181495	190	95.0	78.8
5619239	प्रशांत जैन	322447	190	95.0	78.8
5619441	रविंदर जैन	327293	190	95.0	78.8
494563	शरत थोटा	083223	190	95.0	78.8
5293707	आशीष सांगवान	011764	188.33	94.2	78.1
5597674	रानाधीर अल्लू	136150	187.5	93.8	77.8
2387378	श्रीकांत रेड्डी	188130	187.5	93.8	77.8
5619612	गरूण सुमित सुनील	361061	187.5	93.8	77.8
2387056	प्रतीक वमसी गुर्रम	164567	187.5	93.8	77.8
5597676	मुरलीधर कोमीशेट्टी	033471	187.5	93.8	77.8
5597844	अर्पित शर्मा	103316	187.5	93.8	77.8
3013398	विनीत कुमार	241717	187.5	93.8	77.8
5293702	रतेन्द्र सिंह	006643	186.68	93.3	77.5
5099681	पंकज मित्तल	153106	186.68	93.3	77.5
3012296	अनुदीप दूरीशेट्टी	123528	186.68	93.3	77.5
2387152	प्रेम अकुंला	539516	185.83	92.9	77.1
5597689	आकांश दूबे	020889	185	92.5	76.8
2387786	नरसिम्हा पालाशानी	109847	185	92.5	76.8
3013337	गौरीशंकर डी	404474	185	92.5	76.8

और कई अन्य...

CSAT '15 के लिए CL से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें

सिविल सेवा '13 के टॉप 10 में से 6 CL विद्यार्थी हैं

रैंक 1st

गौरव अग्रवाल
CL पंजीकरण संख्या: 3540934
(सीएल एमबीए प्रेप विद्यार्थी)

रैंक 3rd

रचित राज
CL पंजीकरण संख्या: 1035692

रैंक 6th

साक्षी साहनी
CL पंजीकरण संख्या: 5293711

रैंक 8th

जॉनी टी वर्गीश
CL पंजीकरण संख्या: 5293820

रैंक 9th

दिव्यांशु झा
CL पंजीकरण संख्या: 4088566

रैंक 10th

मेघा रूपम
CL पंजीकरण संख्या: 10017630

और कई अन्य...

80+* CL विद्यार्थियों ने सिविल सेवा 2013 में ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की है

*परिणामों का ऑडिटिंग अभी जारी है

प्रवेश जारी है
GS और CSAT '15 बैच के लिए

/CLRocks

CL Civil Services Test Prep
www.careerlauncher.com/civils

नये बैचों की जानकारी हेतु अपने निकटतम् CL सिविल केंद्र से संपर्क करें

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन – 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर के सामने, फोन – 42375128/29
बेर सराय: 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन – 26566616/17
साउथ कैम्पस: 283, प्रथम तल, वेंकेटेश्वरा कॉलेज के सामने, सत्या निकेतन, फोन – 24103121/39

अहमदाबाद: 9879111881 | इलाहाबाद: (0)9956130010 | बंगलुरू: 41505590 | भोपाल: 4093447 | भुवनेश्वर: 2542322 | चंडीगढ़: 4000666 | चेन्नई: 28154725
हैदराबाद: 66254100 | इन्दौर: 4244300 | जयपुर: 4054623 | लखनऊ: 4108009 | नागपुर: 6464666 | पटना: 2678155 | पुणे: 32502168

KH-133/2014

रेल बजट में यात्री सुविधाओं के साथ विकासात्मक पहलुओं पर जोर

नवनीत रंजन

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट को देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अत्याधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला बताया है। उन्होंने साफ कहा कि इक्कीसवीं सदी का भारत विज्ञान और तकनीक का भारत है ऐसे में रेलवे को तकनीकी रूप से बेहतर बनाना जरूरी है। इस रेल बजट में तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है।

सरकार ने रेल बजट में दूरगामी विकासात्मक तथ्यों को ध्यान में रखा है। त्वरित तौर पर किराया भले कम नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि रेल बजट के जरिए इंफ्रास्टक्चर को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रेलवे 1,64,374 करोड़ रुपये की आय अर्जित करेगा और वर्ष 2014–15 के दौरान 1,49,176 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। संचालन अनुपात के 92.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो वर्ष 2013–14 की तुलना में एक प्रतिशत बेहतर है। रेल बजट 2014–15 में 58 नई ट्रेनों के अलावा मौजूदा 11 ट्रेनों के विस्तार का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रेल बजट में नई लाइनों के लिए 28 सर्वेक्षण और दोहरीकरण का भी प्रस्ताव रखा गया है। पूर्वोत्तर की परियोजनाओं को आर्थिक मदद के साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए विशेष पैकेज ट्रेनें, दो पर्यटक रेल और स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन के लिए एक विशेष ट्रेन का भी प्रस्ताव है।

बजट में यात्रियों की सुविधाओं और समुचित स्टेशन प्रबंधन पर खास ध्यान दिया

गया है। अब सभी प्रमुख स्टेशनों पर पैदल पार पथ पुल, एक्सीलेटर और लिफ्ट की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इससे बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों को स्टेशन परिक्षेत्र में आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसी तरह उपनगरीय कोचों और मुख्य लाइन में स्वचालित दरवाजे लगाने के लिए पायलट परियोजना प्रारंभ किए जाने का भी प्रस्ताव है। रेल बजट में सूचना प्रौद्योगिकी पहलों पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। इंटरनेट पर अनारक्षित टिकटों और प्लेटफार्म टिकटों का भी प्रावधान किया गया है। रेलवे ने ट्रेनों के आवागमन की सही जानकारी और यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित जागरुकता कॉल प्रणाली, मोबाइल आधारित गंतव्य पहुंच अलर्ट और ए–1 तथा ए श्रेणी के स्टेशनों और चुनिंदा रेलों में वाई–फाई सेवाएं देने का भी प्रस्ताव किया है। भारतीय रेल नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने के लिए चुनिंदा 9 क्षेत्रों में 160–200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली ट्रेनों के

अलावा मुंबई–अहमदाबाद क्षेत्र में एक बुलेट ट्रेन का भी प्रस्ताव किया है। रेलवे ने देश के सभी प्रमुख मेट्रो और विकसित केन्द्रों को जोड़ने के लिए त्वरित गति के रेल संपर्क नेटवर्क के लिए डायमंड क्वाड्रिलेटरल परियोजना का भी प्रस्ताव किया है। निश्चित रूप से विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में यह प्रयास मील का पत्थर साबित होंगे। इतना ही नहीं रेलमंत्री ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी के माध्यम से नवीन विकसित हवाई अड्डों की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ चिन्हित स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव यात्रियों को सुविधा तो प्रदान करेगा ही साथ ही विदेशों में भारतीय रेलवे की छवि को निखारने की दिशा में भी अहम कदम है। इसी तरह सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से पार्सल वैनों की खरीद, विशेष दूध टैंक ट्रेनें, सब्जियों और फलों की ढुलाई में तेजी लाने के लिए वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी जैसी सुविधाओं का भी प्रस्ताव है। इन प्रोजेक्ट के परवान चढ़ने पर कृषि प्रधान देश भारत को एक नई ऊर्जा मिलेगी। भारत के किसानों एवं पशुपालकों को काफी लाभ मिलेगा। व्यापारियों को भी फलों एवं सब्जियों के सड़ने–गलने से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा।

इस रेल बजट में तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2014–15 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए रेलमंत्री ने यात्री सुविधाओं में वृद्धि, अधिक सुरक्षा उपाय, परियोजनाओं की समय से समाप्ति और वित्तीय अनुशासन बढ़ाने जैसे मुद्दों पर खास जोर दिया है। रेलमंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने सदन में कहा कि रेलवे में ढांचागत सुधारों को लागू किया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका बढ़ाते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सार्वजनिक, निजी साझेदारी के माध्यम से संसाधनों का विस्तार

भी किया जाएगा। रेलमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल देश का अग्रणी वाहक होने के साथ–साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद और आत्मा भी है। बेंगलुरू की गलियों के एक आम आदमी से लेकर कोलकाता में मछली विक्रेताओं तथा चहल–पहल भरे निजामुद्दीन स्टेशन तक, हर जगह इस देश का नागरिक भारतीय रेलवे से यात्रा करने के लिए बेताब मिलेगा। ऐसी स्थिति में सभी को बेहतर सुविधाएं देना मेरा पहला धर्म है।

महानगरों का ख्याल

रेलमंत्री ने बजट में उपनगरीय और महानगरों के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई अहम प्रावधान किए हैं। इसके तहत अगले दो वर्षों में मुंबई में अत्याधुनिक 864 अतिरिक्त ईएमयू चलाने का प्रस्ताव है। जबकि बेंगलुरू से दूसरे इलाके के रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए अध्ययन कराने की बात कही गई है।

ई–टिकटिंग

रेल बजट में ई–टिकट प्रणाली की क्षमताओं में सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके जरिए 2,000 टिकट प्रति मिनट की तुलना में 7200 टिकट प्रति मिनट उपलब्ध हो सकेंगे। सिक्के डालकर परिचालित होने वाली ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों की सुविधा का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही इंटरनेट के जरिए प्लेटफार्म टिकट और अनारक्षित टिकट खरीदने की सुविधा भी मिलेगी। पार्किंग–सह–प्लेटफार्म काम्बो टिकट भी शुरू किए जाएंगे। सभी स्टेशनों पर रेलवे विश्रामालयों की ऑन लाइन बुकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी

सूचना एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष के दौरान रेल कंप्यूटर असिस्टड एंटरप्राइस रिसोर्स प्लानिंग सोल्युशन भी शुरू किया जाएगा। रेलमंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय रेल को 5 वर्षों के भीतर कागज रहित कार्यालय बनाने की ओर अग्रसर है। ए1 और ए कोटि के सभी स्टेशनों और चुनिंदा ट्रेनों में वाई–फाई सेवाएं, ट्रेनों और चल स्टॉक की रियल टाइम ट्रैकिंग, यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित वेकअप कॉल प्रणाली की सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

खानपान गुणवत्ता

ट्रेनों में खानपान गुणवत्ता सुधारने के लिए रेलमंत्री ने प्रतिदिन ब्रांडों का पहले से तैयार किया हुआ भोजन (रेडी टू ईट) शुरू करने का प्रस्ताव किया है। एनएबीसीबी प्रमाणित एजेंसियों द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए गुणवत्ता परखेंगे। इसके साथ ही यात्रियों को परोसे गए भोजन पर आईवीआरएस तंत्र के जरिए यात्रियों से फीडबैक प्राप्त करने की प्रणाली शीघ्र ही शुरू की जाएगी। ऐसे में यदि सेवा विशेष रूप से स्वच्छता और स्वाद के मामले में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होगी तो ठेकों को रद्द करने सहित वेंडरों के विरुद्ध कार्रवाही की जाएगी। प्रमुख स्टेशनों पर फूड कोर्ट स्थापित होगा। इससे ईमेल, एसएमएस और स्मार्ट फोन आदि के जरिए स्थानीय भोजन का ऑर्डर देने का विकल्प मिल सकेगा। नई दिल्ली–अमृतसर और नई दिल्ली–जम्मू तवी खंडों के बीच पायलट परियोजना शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

बजट की खास बातें

- 1,64,374 करोड़ रुपये की कुल आमदनियां होंगी तो 1,49,176 करोड़ रुपये का खर्चा निर्धारित किया।
- माल यातायात में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि। इससे 1,05,770 करोड़ रुपये की आय का अनुमान।
- मासिक सीजन टिकट के किरायों में संशोधन करने संबंधी उपनगरीय यात्रियों के अनुरोध पर विचार।
- यात्री किरायों और मालभाड़े में आवधिक संशोधन को ईंधन की कीमतों के संशोधनों से जोड़ा जाएगा ताकि ईंधन की लागत में वृद्धि से रेलवे राजस्व को सुरक्षित रखा जा सके।
- कुल व्यय में से साधारण संचलन व्यय 1,12,649 करोड रुपये प्रस्तावित।
- ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 4000 महिला आरपीएफ कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी।
- ई–टिकिटिंग, प्रमुख स्टेशनों और चुनिंदा रेलों में वाई–फाई सेवाएं दी जाएंगी।
- यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित जागरुकता कॉल के माध्यम से नई पीढ़ी के लिए रेलवे की आरक्षण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव।
- 58 नई ट्रेनें, 11 मौजूदा ट्रेनों का विस्तार।
- रेल विश्वविद्यालय और अभिनव इनक्यूबेशन केंद्र का गठन किया जाएगा।
- अगले दो महीनों में वैगनों का ऑनलाइन पंजीकरण।
- रेल नेटवर्क विस्तारीकरण पर करीब 9 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- एक बुलेट ट्रेन चलाने में लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना

रेलमंत्री ने तकनीकी और गैर–तकनीकी दोनों विषयों के लिए रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया।

स्नात्तक–स्तर पर रेलवे से संबंधित विषयों को चालू करने और कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता किया जाएगा। फिलहाल, ग्राउंड लेवल के कर्मचारियों को स्थानीय तकनीकी संस्थानों में इस्तेमाल करके तकनीकी और गैर–तकनीकी किस्म के अल्पावधि पाठयक्रमों के लिए भेजा जाएगा। उच्च रफ्तार, भारी–कर्षण परिचालन आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने के लिए सभी स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को भारत तथा विदेश में उपयुक्त संस्थानों में भेजा जाएगा।

कर्मचारियों का रखा ध्यान

रेलमंत्री श्री डी.वी सदानंद गौड़ा ने कहा कि जल्द ही अभिनव इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर में भारतीय रेलकर्मियों के विचारों को लिया जाएगा और सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों की नूतन सोच से लागत में बचत होगी और साथ ही राजस्व का सृजन होगा उन्हें प्रोत्साहन के रूप में समुचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। रेल बजट में यात्रियों के साथ ही रेलकर्मियो के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बजट में कर्मचारी हित निधि में 500 रुपये प्रति व्यक्ति राशि के अंशदान को बढ़ाकर 800 रुपये प्रति व्यक्ति के रूप में करने का प्रस्ताव है। शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा सराहनीय कार्य निष्पादन करने पर उनके लिए विशेष योजना की घोषणा करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सभी स्वास्थ्य इकाइयों, मंडल स्तर के अस्पतालों और सेंट्रल अस्पतालों के साथ–साथ पैनलबद्ध अस्पतालों को एकीकृत करने के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। लोको केबिनों में वातानुकूलन की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है।

छात्रों के लिए भी

रेलमंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्टडी के अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप स्थापित की जाएगी। छात्र रेलों की किसी भी इकाई अर्थात् मंडलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उत्पादन इकाइयों पर इंटर्नशिप कर सकते हैं।

साफ–सफाई बजट बढ़ोतरी

रेलमंत्री ने चालू वर्ष में साफ–सफाई के लिए करीब 40 फीसदी बजट बढ़ा दिया है। देश के 50 बड़े स्टेशनों पर साफ–सफाई गतिविधियों को आउटसोर्स कर व्यावसायिक एंजेसियों द्वारा कराने के साथ ही अलग से हाऊसकीपिंग विंग स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह विंग स्टेशनों पर साफ–सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देगा और स्वच्छता बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निभाएगा। स्टेशनों पर साफ–सफाई बनाए रखने के लिए स्टेशन पर एक कॉर्पस फंड की व्यवस्था की जाएगी। साफ–सफाई संबंधी गतिविधियों की निगरानी के लिए स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सभी पीआरएस टिकटों के पीछे अखिल भारतीय स्तर के शिकायत हेल्पलाइन नंबर मुद्रित किए जाएंगे। आवधिक थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रणाली शुरू की जाएगी। इसके अलावा, स्टेशनों पर रेलपथों और प्लेटफार्मों के साथ ही ट्रेनों में जैविक शौचालयों को बढ़ाया जाएगा।

पेयजल सुविधा

स्टेशनों और ट्रेनों में पीने के पानी के लिए आरओ यूनिट लगाने की भी प्रायोगिक तौर पर शुरुआत की जाएगी। स्टेशनों को गोद लेने और वहां पर बेहतर स्वच्छता एवं साफ–सफाई बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठित और इच्छुक गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), चैरिटेबिल संस्थानों और कॉरपोरेट घरानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

फर्राटा भरेगी बुलेट ट्रेन

रेलमंत्री डी.वी सदानंद गौड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि उच्च रफ्तार परियोजना के लिए उच्च रफ्तार रेल गलियारा शुरू किया जाएगा। इस पर करीब 100 करोड़ रु. खर्च होगा। मुंबई–अहमदाबाद खंड पर बुलेट ट्रेन

चलाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कई अध्ययन किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली–आगरा, दिल्ली–चंडीगढ़, दिल्ली–कानपुर नागपुर–बिलासपुर, मैसूर–बेंगलूरू–चेन्नै, मुंबई–गोवा, मुंबई–अहमदाबाद, चेन्नई–हैदराबाद, और नागपुर–सिकंदराबाद रूट पर 160–200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड की ट्रेनें चलाने का प्रयास किया जाएगा।

स्टेशन प्रबंधन

यात्री सुख–सुविधाओं के रूप में भारतीय रेल के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पीपीपी के माध्यम से ऊपरी पैदल पुल, एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर पानी की आपूर्ति, प्लेटफार्म शेल्टर, शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी चालित कार्ट की शुरुआत की जाएगी।

मुंबई के लिए दो वर्ष में 864 अत्याधुनिक ईएमयू

बजट में मुंबई शहर को दो वर्ष की अवधि में 864 अतिरिक्त अत्याधुनिक ईएमयू ट्रेनें देने का प्रस्ताव किया गया है। बैंगलुरू क्षेत्र में भी यात्री यातायात की मांग को पूरा करने के लिए बायाप्पनाहल्ली को कोचिंग टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा बैंगलुरू के मौजूदा भारतीय रेल नेटवर्क के संवर्धन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा।

भूमि परिसंपत्तियों का डिजिटलाइजेशन

रेलमंत्री ने रेलमंत्री ने कहा है कि भारतीय रेल की भूमि परिसंपत्तियों का डिजिटलाइजेशन और उसकी जीआईएस मैपिंग करने की जरूरत है ताकि उसका बेहतर प्रबंधन और इस्तेमाल हो सके। रेलवे को इस भूमि की सुरक्षा और संसाधनों में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग करने में सहायता मिलेगी। रेलवे भूमि पर रेलवे से संबंधित कारोबार शुरू करने और साथ ही वाणिज्यिक विकास के लिए निजी भागीदारी के माध्यम से भूमि–संपदा का इस्तेमाल करके संसाधन जुटाने की संभावना का पता लगाया जाएगा।

सुरक्षा और संरक्षा में सुधार

रेलमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि रेलपथ नवीकरण, बिना चौकीदार वाले समपारों को समाप्त करने और निचले सड़क पुल एवं ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए प्रत्येक वर्ष 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी। इस बजट में निचले सड़क पुल एवं ऊपरी सड़क पुल के लिए 1,785 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। रेलमार्ग पर 30,348 समपार हैं, जिनमें से 11,563 बिना चौकीदार वाले हैं। बिना चौकीदार वाले प्रत्येक समपार की विस्तृत जांच की जा रही है और स्थान की स्थिति के आधार पर उसे उपयुक्त माध्यमों द्वारा समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलों की पटरियों और वेल्डिंग की टूट–फूट का पता लगाने के लिए आधुनिक व्हीकल बोर्न अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पायलट परियोजना के रूप में दो स्थानों पर अल्ट्रासोनिक ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम (यूबीआरडी) का भी परीक्षण किया जाएगा। मेन लाइन और उपनगरीय सवारी डिब्बों, दोनों में गाड़ी के चलने से पहले स्वतः दरवाजे बंद होने की प्रौद्योगिकी लाने का प्रस्ताव है ताकि यात्रियों की संरक्षा में सुधार किया जा सके। कुछ चुनिंदा गाड़ियों में पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही 17,000 रेल सुरक्षा बल कांस्टेबलों की भर्ती की जा रही है और शीघ्र ही उनकी तैनाती कर दी जाएगी। 4000 महिला रेल सुरक्षा बल कांस्टेबलों की भर्ती का भी प्रस्ताव है। ट्रेनों के रेल सुरक्षा बल के मार्गदर्शी दलों को मोबाइल फोन मुहैया कराया जाएगा ताकि रेल यात्री परेशानी में उनसे संपर्क कर सकें। सुरक्षा हेल्पलाइन को बेहतर किया जाएगा।

रेल पर्यटन को प्रोत्साहन

देश में घरेलू पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी रेल बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में ईको–टूरिज्म और एजुकेशन टूरिज्म शुरू करने की योजना है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के लिए देवी सर्किट, ज्योतिर्लिंग सर्किट, जैन सर्किट, क्रिश्चन सर्किट, मुस्लिम–सूफी सर्किट, सिख सर्किट, बोध सर्किट, प्रसिद्ध मंदिर सर्किट आदि

जैसे विशेष तीर्थ सर्किटों की पहचान की गई है। इन सर्किटों के लिए विशेष पैकेज गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए कम दूरी की कुछ गाडियां शुरू करने का भी इरादा है। इसके तहत बागलकोट, बीजापुर और सोलापुर के रास्ते गदग से पंढरपुर तक एक पर्यटन ट्रेन चलाई जाएगी जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के तीर्थ–स्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। दूसरी ट्रेन रामेश्वरम से चलाई जाएगी जोकि बेंगलुरू, चेन्नई, अयोध्या, वाराणसी और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। स्वामी विवेकानंद के नैतिक मूल्यों और उनके उपदेशों का प्रचार करने लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन और कार्य का प्रचार करने वाली एक विशेष गाड़ी चलाने की भी योजना है।

पूर्वोत्तर में रेल विस्तार

रेलमंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 23 परियोजनाएं प्रगति पर है, जिनमें 11 राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। वर्ष 2014–15 में पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 5,116 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह धनराशि पिछले वर्ष के आबंटन से 54 प्रतिशत अधिक है। इस आबंटन से इस क्षेत्र में कार्यों की निगरानी के अलावा दुधनोई–मेंदीपठार नई लाइन, लमडिंग–बदरपुर–सिलचर आमान परिवर्तन, हरमुटी–मुर्कोंगसलेक और बालीपाड़ा–भालुकपोंग खंडों को शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। इन उपायों से इस क्षेत्र में राज्य की राजधानी को जोड़ने संबंधी परियोजनाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

परियोजना प्रबंधन समूह की स्थापना

परियोजना के निष्पादन में होने वाली देरी से बचने के लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर परियोजना प्रबंधन समूह की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें राज्य सरकार, रेलवे के पदाधिकारी और पेशेवर शामिल होंगे।

10 स्थानों पर तापमान नियंत्रित भंडारण

बजट में 10 स्थानों पर तापमान नियंत्रित भंडारण सुविधा देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत पहले चरण में भारतीय रेल के 10 स्थानों वत्वा, विशाखापट्टनम, बडगरा, चेरियानड, भिवंडी रोड, अजरा, नव्लुर, कलंबोली और सानंद पर तापमान नियंत्रित भंडारों की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था से सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीआरडब्ल्यूसी) के साथ भागीदारी में फलों और सब्जियों की रेल द्वारा ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा।

सौर ऊर्जा और बायो डीजल का उपयोग

रेलवे स्टेशनों, रेलवे इमारतों की छतों और भूमि का सार्वजनिक और निजी साझेदारी के माध्यम से उपयोग कर 500 मेगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करने का प्रस्ताव है। भारतीय रेल, डीजल इंजनों के कुल ईंधन उपभोग के पांच प्रतिशत तक बायो डीजल का उपयोग करना शुरू करेगी। इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी।

18 नई लाइनों का दोहरीकरण

रेलमंत्री ने वर्ष 2014–15 में नई लाइनों के लिए 18 सर्वेक्षण, दोहरीकरण–तीसरी लाइन–चौथी लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए 10 सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : navneetrnjn955gmail.com

आलू की उन्नतशील खेती

डॉ. वीरेन्द्र कुमार

कम अवधि में तैयार होने व भोजन देने के साथ-साथ आलू दुनिया भर में रोजगार देने में भी अग्रणी रहा है। निकट भविष्य में भारत सबसे बड़ा आलू निर्यातक देश होने जा रहा है। आलू कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। यही कारण है कि किसान भाई आलू की खेती करके जहां भरपूर मुनाफा कमाते हैं वहीं छोटे किसानों के लिए यह दोहरा फायदा देती है। लघु और सीमांत किसान आलू की खेती करके अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ आलू की खुदाई उपरांत गेहूं, मूंग, लोबिया, प्याज व अन्य फसलें ले सकते हैं। गत कई वर्षों से आलू का मूल्य अच्छा होने की वजह से किसानों को पर्याप्त मुनाफा मिल रहा है।

विश्व की सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली सब्जियों में आलू का महत्वपूर्ण स्थान है। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे अधिकांश सब्जियों में मिलाकर खाया जाता है। आलू हमारे देश की महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसलों में से एक है। भारत में आलू फसल विविधीकरण, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और खाद्य तथा पोषक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आलू एक अत्यधिक उत्पादित फसल है जो देश में प्रचलित विभिन्न फसल प्रणालियों के साथ समायोजित हो सकती है। कम अवधि में तैयार होने व भोजन देने के साथ–साथ आलू पूरी दुनिया में रोजगार देने में भी अग्रणी रहा है। निकट भविष्य में भारत सबसे बड़ा आलू निर्यातक देश होने जा रहा है। वर्ष 2011–12 में पूरे भारत में आलू की उत्पादकता 22.3 टन प्रति हेक्टेयर रही। भारतीय आलू का निर्यात श्रीलंका, बर्मा, भूटान व नेपाल में किया जा रहा है। आलू को उत्तर भारत में परम्परागत रूप से सब्जी के रूप में खाया जाता है। जबकि दक्षिण भारत में डोसे, महाराष्ट्र में बडा पाव व आलू कचौड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। गत कई वर्षों से आलू का मूल्य अच्छा होने की वजह से किसानों को पर्याप्त मुनाफा मिल रहा है। आपूर्ति मांग से ज्यादा होने के कारण किसानों को निराशा हाथ लगती है। आलू का निर्यात जारी रहना, राज्यों का समय रहते आलू की खरीद न करना और तूफान व भारी बारिश के कारण फसल खराब होना। आलू की फसल उत्पादों का ज्यादा समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इस कारण किसानों को कम दामों पर भी आलू बेचना पड़ता है।

पौष्टिकता – आलू पोषक तत्वीय गुणों से भी भरपूर है। आलू में सभी अधिकांश पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आलू में उपस्थित प्रोटीन की बायोलोजिकल वैल्यू अंडा और दूध में पायी जाने वाली प्रोटीन के बराबर है। आलू केरोटिनाइड और एंटीआक्सीडेंटस का भी मुख्य स्रोत है। आलू से मोटापा नहीं बढ़ता है क्योंकि यह कम ऊर्जा व कम वसायुक्त खाद्य है। उबले हुए आलुओं में गेहूं के बाद सबसे अधिक फोलिक एसिड पाया जाता है। आलू विटामिन सी का भी प्राकृतिक स्रोत है। यह शाकीय प्रोटीनों में से एक है जिसकी तुलना जीव उत्पादित प्रोटीनों से की जा सकती है। भारत व अन्य देशों में भुखमरी मिटाने में यह चावल, गेहूं और मक्का के बाद महत्वपूर्ण फसल है। दुनियाभर में इसे विविध रूपों में खाया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर आलू सरलता से पचता है। इसमें खनिज लवणों के अलावा उच्च गुणवत्ता का पाचन योग्य रेशा पाया जाता है। किसी भी अन्य सब्जी या अनाज की तुलना में आलू में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का अनुपात अधिक पाया जाता है। आलू को आटे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विश्व में भुखमरी व कुपोषण मिटाने में भी आलू का उत्कृष्ट रिकार्ड रहा है। साथ ही इसका आहार सस्ता व पौष्टिक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की भरूपर मात्रा के अलावा खनिज लवण, विटामिन एवं अमीनो एसिड पाए जाते हैं।

आलू का पोषक तत्वीय संघटन

क्रमांक	पोषक तत्व	मात्रा (प्रतिशत में)	क्रमांक	पोषक तत्व	मात्रा (प्रतिशत में)
1.	पानी	75–80	7.	फास्फोरस	40.0 मि.ग्रा.
2.	कार्बोहाइड्रेट	16–20	8.	रेशा	0.4 ग्राम
3.	प्रोटीन	2.0–2.5	9.	कैलोरी	97 कि.कैलोरी
4.	वसा	0.15	10.	सोडियम	11.0 मि.ग्रा.
5.	खनिज लवण	1.0	11.	आयरन	0.70 मि.ग्रा.
6.	कैल्शियम	10.0 मि.ग्रा.	12.	विटामिन–बी	0.01 मि.ग्रा.

वितरण व क्षेत्र – आलू का उत्पत्ति स्थान लेटिन अमेरिका (पेरू) माना जाता है। आलू की फसल की खोज 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। पूरी दुनिया में आलू की पैदावार प्रतिवर्ष 30 करोड़ टन से अधिक होती है। विश्व में सबसे अधिक आलू चीन में पैदा होता है। इसके बाद रूस और तीसरे स्थान पर भारत का नम्बर है। दुनियाभर में एक अरब से अधिक लोग आलू खाते हैं। सबसे ज्यादा आलू बेलारूस में खाया जाता है। वर्तमान में दुनिया का आधा आलू विकासशील देशों में पैदा होता है। पूरे यूरोप में आलू मुख्य भोजन है। आलू की फसल लगभग 150 देशों में उगायी जाती है। विश्व में आलू का क्षेत्रफल 18.6 मिलियन हेक्टेयर है जिससे 321 मिलियन टन आलू का उत्पादन होता है। विश्व में आलू की उत्पादकता 17.25 टन प्रति हेक्टेयर है। आलू को परम्परागत रूप से सब्जी के रूप में उगाया व खाया जाता है। भारत में आलू की प्रति व्यक्ति सालाना खपत केवल 20 किलोग्राम है। धान, गेहूं, मक्का के बाद आलू दुनिया की चौथे नम्बर की फसल है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां के रसोईघर में आलू की खपत न होती हो। आलू का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी गेहूं व धान की अपेक्षा दो से चार गुना अधिक होता है। आलू का उत्पादन देश के लगभग सभी भागों में हो रहा है जिनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पंजाब इन चारों प्रदेशों में सम्पूर्ण भारत का 86 प्रतिशत उत्पादन होता है। जिन राज्यों में अभी तक आलू की खेती नहीं होती थी वहां पर भी आलू की खेती का प्रचलन दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में 97 प्रतिशत आलू सिर्फ 10 राज्यों में पैदा होता है। इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 33 प्रतिशत आलू की पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, आगरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में आलू की खेती सर्वाधिक की जाती है। यह पूरा क्षेत्र आलू बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आलू उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल व बिहार की हिस्सेदारी क्रमशः 31.4 व 13.5 प्रतिशत है।

वानस्पतिक विवरण – आलू सोलेनेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। वानस्पतिक रूप से आलू एक मांसल तना है। जिसका उत्पादन रूपान्तरित कन्द द्वारा होता है। इसका तना बेलनाकार, मांसल व पतला होता है। इसके पौधे 35–50 से.मी. लम्बे होते हैं। इसमें किस्मों के अनुसार सफेद या बैंगनी रंग के फूल होते हैं। आलू के पौधों में फूल तथा फल केवल ठंडे स्थानों पर बनते हैं। यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में अधिक फूल बनते हैं। जबकि आलू सामान्यतः एक स्वपरागित फसल है। सर्दी के दिनों में मैदानी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है।

जलवायु – आलू की फसल की विशेषता यह है कि इसे ठंडे मौसम और ऊंचाई पर आसानी से उगाया जा सकता है। आलू की उचित वृद्धि व विकास हेतु जलवायु न अधिक गर्म और न अधिक ठंडी होनी चाहिए। बीज के अंकुरण व प्रारम्भिक बढ़वार के समय 25 डिग्री सें. तापमान उपयुक्त माना जाता है। जबकि कन्दों के निर्माण और इनकी वृद्धि हेतु 18–20 डिग्री.सें. तापमान की आवश्यकता होती है। यह शीतोष्ण क्षेत्र की फसल है परन्तु उष्ण–कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में भी रबी फसल के रूप में आसानी से उगायी जा सकती है।

उन्नतशील प्रजातियां – हिमाचल प्रदेश के शिमला में केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने कुफरी श्रेणी की 45 के लगभग किस्में विकसित करके आलू क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज विश्व में आलू की लगभग 5000 किस्में हैं। जो अधिकतर एंड़ीस पहाड़ियों पर उगती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र के जीन बैंक में ये सभी किस्में सुरक्षित हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने गत 10–15 वर्षों में आलू की ऐसी किस्मों को विकसित किया है जिनमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा है। लेकिन क्षेत्रीय/अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन नहीं होने के कारण इनका व्यावसायिक उत्पादन नहीं हो रहा है। विश्वभर में आलू की सैंकड़ों प्रजातियां उगाई जाती हैं। हर वर्ष कई नई प्रजातियों का विकास होता है। आलू की प्रमुख प्रजातियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है –

कुफरी चन्द्रमुखी – यह अगेती प्रजाति है जो उत्तर भारत व मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह 70–90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके कन्द सफेद रंग के और इसकी औसत उपज 150–200 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है।

कुफरी जवाहर (जे.एस.–222) – यह उत्तरी भारत में बुवाई हेतु उपयुक्त है। यह मध्यम अवधि की फसल है जो 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके कंद सफेद रंग के व उपज 200–250 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है।

कुफरी पुखराज – यह किस्म अगेती झुलसा के प्रति अवरोधी है। इसकी औसत पैदावार 300–350 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। यह मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है।

कुफरी सिन्दूरी – यह उत्तर–पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में समय से बुवाई हेतु उपयुक्त प्रजाति है। इसे नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक बोने पर भी अच्छी उपज मिल जाती है। इसकी औसत उपज 250–250 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। यह पछेती झुलसा अवरोधी व 100–110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।

कुफरी गिरिराज – यह किस्म पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। यह लगभग 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह पछेती झुलसा के प्रति सहनशील है। इसकी औसत उपज 200–250 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है।

कुफरी बादशाह – यह पछेती किस्म है जो 100–120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।

कुफरी शीतमान – यह काला रूसी अवरोधी किस्म है। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई के तथा कन्द अण्डाकार एवं सफेद रंग के होते हैं। इसकी औसत उपज 200–250 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है।

कुफरी सतलुज (जे.आई.–8557) – यह मध्यम अवधि में तैयार होने वाली प्रजाति है जो 100–110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके कन्द सफेद रंग के व औसत उपज 200–250 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। पछेती बुवाई (15 नवम्बर से 31 दिसम्बर) हेतु उपयुक्त है।

चिपसोना–1 – इसके कन्द अण्डाकार, सफेद रंग के व चिकने होते हैं। इसके कन्द चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इसकी पैदावार 150–200 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होती है। यह उत्तरी भारत में बुवाई हेतु उपयुक्त किस्म है।

चिपसोना–2 – इसके कन्द गोल, सफेद रंग के, चिकने व अण्डाकार होते हैं। इसकी उपज 200–250 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होती है। यह चिप्स बनाने के लिए उत्तम किस्म है।

चिपसोना–3 – प्रायः सभी कन्द एक समान आकार के, सफेद, चिकने व अण्ड़ाकार होते हैं। इसकी उपज 200–250 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होती है। यह चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त प्रजाति है।

कुफरी ज्योति – इसके पौधे लम्बे, सीधे तथा अच्छी वृद्धि वाले होते हैं। यह प्रजाति लगभग 100 दिनों में खुदाई हेतु तैयार हो जाती है। यह सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। इसकी औसत पैदावार 250–300 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है।

कुफरी बहार – यह मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी फसल अवधि 90–100 दिन की होती है। इसकी औसत उपज 300–500 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है।

कुफरी सूर्या – उत्तर–पश्चिम भारत के सिंचित मैदानी क्षेत्रों में आलू की अगेती बुवाई हेतु उपयुक्त है। इसकी बुवाई का उपयुक्त समय 15–30 सितम्बर के बीच है। यह प्रजाति 100–110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज 200–250 कुन्तल प्रति हैक्टेयर मिल जाती है। यह फ्रेंचफ्राई हेतु उपयुक्त किस्म है।

अटलांटा – आलू की यह किस्म पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। इस किस्म का इस्तेमाल मुख्य रूप से चिप्स बनाने में किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में मुख्य तौर पर आलू की इस किस्म की खेती की जाती है।

फसल चक्र – मार्च में आलू की कटाई उपरान्त खेत खाली हो जाते हैं। अतः नई फसलों की बुवाई हेतु खेत तैयार करने का भी यह उपयुक्त समय है। अधिक लाभ व संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए इस समय सूरजमुखी, ग्रीष्मकालीन मूंगफली, बसन्तकालीन गन्ना, बसन्तकालीन/ग्रीष्मकालीन मूंग ,सब्जियों, फूलों व हरे चारे वाली फसलों की बुवाई की जा सकती है।

बीज का चुनाव – आलू का बीज किसी मान्यता प्राप्त व

विश्वसनीय संस्थाओं, सरकारी संस्थानों अथवा बीज निगमों से ही खरीदें। अच्छे जमाव हेतु 30–40 ग्राम वजन के कन्दों का प्रयोग करें। बुवाई से 10 दिन पहले आलू के बीज को ठंडे गोदाम से निकाल लें। पहले बीज को 24 घंटे के लिए प्रीकूलिंग चेम्बर में रखें। इसके बाद बीज को कन्द फुटाव हेतु छाया वाली जगह पर रखें। समय–समय पर बीज का निरीक्षण कर सड़े हुए, कटे–फटे, रोगग्रस्त व बिना अंकुरित हुए आलुओं को निकाल दें। आलू का बीज तीन–चार वर्ष बाद अवश्य बदल दें अन्यथा बीज में विषाणु रोग बढ़ने की सम्भावना बढ़ जाती है।

बुवाई का समय – उत्तर भारत में आलू की बुवाई का उपयुक्त समय अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जिन स्थानों में दिसम्बर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में पाला पड़ता है, वहां पर पाला पड़ने तक आलू की फसल को वृद्धि व विकास के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यह फसल फरवरी के आखिर से मार्च के मध्य तक तैयार हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आलू की बुवाई मार्च–अप्रैल तथा घाटियों में फरवरी माह में की जाती है।

पहाड़ी क्षेत्र–मार्च से जून

खरीफ–जून–जुलाई

मैदानी क्षेत्र अगेती फसल –सितम्बर से अक्तूबर,

मैदानी क्षेत्र मुख्य फसल –नवम्बर

मैदानी क्षेत्र पछेती फसल –दिसम्बर।

बीज की मात्रा – एक हेक्टेयर क्षेत्र में 30–40 ग्राम वजन के आलू की बुवाई हेतु लगभग 25–30 कुन्तल बीज की आवश्यकता होती है।

भूमि – आलू लगभग सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। परन्तु आलू की भरपूर पैदावार हेतु जीवांशयुक्त उचित जलनिकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। पानी ठहरने वाली क्षारीय मिट्टी में आलू की खेती नहीं करनी चाहिए। आलू की अच्छी पैदावार के लिए 6.5–7.5 पी.एच. मान वाली मृदाएं उपर्युक्त मानी जाती हैं।

बुवाई की विधि – आलू की बुवाई मेड़ों के ऊपर की जाती है। जहां तक हो सके मेड़ें 50–60 से.मी. की दूरी पर बनानी चाहिए। बीज को मेड़ की उत्तरी ढलान पर 20–25 से.मी. की दूरी पर बोना चाहिए। आजकल श्रमिकों की कमी के कारण आलू की बुवाई 'पोटेटो प्लान्टर' की मदद से की जाती है जिनमें मेड़ें बनाने और बुवाई का कार्य साथ–साथ किया जाता है। साथ ही इस मशीन द्वारा बुवाई करने पर पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मशीन द्वारा बुवाई करने पर पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी भी आसानी से नियन्त्रित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आलू की बुवाई में परिश्रम, धन व समय की भी बचत होती है। आलू की बुवाई 8–10 से.मी. की गहराई पर करनी चाहिए। भरपूर उपज हेतु एक हेक्टेयर क्षेत्र में आलू के लगभग 84000 पौधे होने चाहिए। बीज वाली फसल में दो प्रजातियों के बीच 5 मीटर की दूरी रखें।

बीज उपचार – बीज को बुवाई से पूर्व 0.1: बाविस्टीन या अन्य फंफूदीनाशक तथा 2.5: बोरिक एसिड के घोल में उपचारित कर लेना चाहिए।

खाद एवं उर्वरक प्रबन्धन – आलू अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल है। अतः इसके लिए 120 : 80 : 100 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। जहां तक हो सके उर्वरकों व खादों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। नाइट्रोजन उर्वरकों की आधी मात्रा व फास्फोरस और पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा बुवाई से पूर्व मेड़ बनाने से पहले सम्पूर्ण खेत में समान रूप से छिटक देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा बुवाई के 20–25 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने से पहले या सिंचाई देने के बाद प्रयोग करनी चाहिए। किसान भाई गोबर की खाद व जैविक उर्वरकों का प्रयोग 8–10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 15–20 दिन पूर्व कर सकते हैं। गोबर की खाद या कम्पोस्ट खाद की मात्रा के अनुसार उर्वरकों की मात्रा घटाई जा सकती है। ध्यान रहे प्रोसेसिंग वाली प्रजातियों को दूसरी किस्मों की अपेक्षा अधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्रमशः 270 : 80 : 170 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। इसके अलावा फसल 4–6 सप्ताह की होने पर खड़ी फसल में दो बार सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक व आयरन का छिड़काव करें।

सिंचाई प्रबन्धन – आलू अधिक पानी चाहने वाली फसल है। सामान्यतः आलू को 7–10 सिंचाई की जरूरत होती है। अतः आलू की खेती अच्छी नमी वाली जमीन में ही करनी चाहिए। आलू की फसल में हल्की व जल्दी–जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई करने समय किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि मेड़ों का दो–तिहाई हिस्सा ही पानी में डूबे। आलू की फसल में प्रथम सिंचाई पौधे उग आने के करीब 15–20 दिन बाद करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 15 दिन बाद करें। आलू की फसल में कन्द बनने की अवस्था नमी की कमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इस अवस्था पर पानी की कमी का आलू की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा नमी व मौसम के अनुसार फसल में 10–15 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सामान्यतः एक कि.ग्रा. आलू पैदा करने के लिए 500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। आलू की खुदाई

से 10 दिन पूर्व सिंचाई बन्द कर देनी चाहिए।

निराई–गुड़ाई – आलू बोने के 20–25 दिनों बाद जब पौधे 10–15 से.मी. ऊंचाई के हो जाएं तो खरपतवार निकालने व मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहिए। इसी समय नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा का भी प्रयोग करना चाहिए। रबी खरपतवारों के नियंत्रण हेतु आलू बोने से पहले खेत का पलेवा करना चाहिए जिससे अधिकांश खरपतवारों के बीज अंकुरित हो जाते हैं जिन्हें जुताई द्वारा नष्ट किया जा सकता है। आलू बुवाई से पूर्व फ्लूक्लोरेलिन (45 ई.सी.) नामक शाकनाशी का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसकी 0.7–1.0 किग्रा. सक्रिय मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। यदि बुवाई से पूर्व किसी कारणवश शाकनाशी का प्रयोग नहीं कर पाए हो तो आलू की बुवाई के 3–5 दिन बाद मृदा में मैट्रीब्यूजिन 70 प्रतिशत डब्ल्यू.पी (500 ग्राम), पेन्डीमिथेलीन 30 ई.सी. की (1 लीटर), एलाक्लोर (1 लीटर) या आक्सीएल्यूरोफोन की 150–200 ग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर रबी खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण व शाकनाशी के अच्छे परिणाम के लिए मृदा में पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक है। आलू में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा का क्रांतिक समय बुवाई के 20–40 दिन बाद है।

पाले से बचाव – उत्तर–पश्चिम भारत में दिसम्बर के अन्त व जनवरी के प्रथम सप्ताह में पाला पड़ने की सम्भावना बनी रहती है। यदि इस समय पाला पड़ने की सम्भावना हो तो आलू की खड़ी फसल में तुरन्त सिंचाई करें। खेतों में रात को ही हवा की दिशा के अनुसार धुंआ करके पाले से फसल को बचा सकते हैं।

आलू का रोग व कीटों से बचाव – आलू की पछेती फसल में यदि झुलसा रोग के लक्षण नजर आएं तो 0.2 प्रतिशत इड़ोफिल–45 नामक दवा का स्प्रे करें। बीज आलू को माहू के प्रकोप से बचाने के लिए फोरेट 10जी 10 किग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी चढ़ाते समय प्रयोग करें।

तनों की कटाई – बीज वाले आलू के लिए तनों को भूमि की सतह से अवश्य काटना चाहिए। खाने वाले आलू में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। खुदाई के लगभग 15–20 दिन पूर्व आलू के तने काट देते हैं जिससे आलू के छिलके सख्त हो जाएं और बीज के लिए आलू खराब न हो। तने काटने के 7–10 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। पैराक्वाट नामक शाकनाशी की 2.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 5–7 दिन के अन्तराल पर दो बार छिड़काव करके भी तनों को नष्ट किया जा सकता है।

आलू की देखरेख – आलू की खुदाई करने के बाद कंदों को सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखें। इसके लिए आलू के ढेरों को मिट्टी की हल्की परत या तिरपाल से ढक कर रखें। सूर्य के प्रकाश के सीधे सम्पर्क में आने पर आलू में 'सोलेनिन' नामक विषैले पदार्थ का निर्माण हो जाता है जिससे आलू की ऊपरी सतह हरे रंग की हो जाती है। जिसका बाजार भाव तो कम मिलता ही है, यह आलू स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होता है। सोलेलिन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। सामान्यतः आलू में इसकी मात्रा 10 मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम पायी जाती है। परन्तु जब इसकी मात्रा 20 मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम से ज्यादा हो जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हरे आलुओं में सोलेनिन की मात्रा के कारण उनमें कुछ कसैलापन भी आ जाता है।

आलू की खुदाई – उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आलू की खुदाई का काम मार्च के तीसरे हफ्ते तक अवश्य पूरा कर लें अन्यथा आलू सड़ना शुरू हो जाता है। जब पत्तियां पीली पड़ जाएं या सूख जाएं व आलू की का छिलका कड़ा हो जाएं तब ही आलू की खुदाई करनी चाहिए। आलू की खुदाई फावड़े या खुरपी से न करके मशीन द्वारा की जाए तो इससे न केवल समय, धन व परिश्रम की बचत होती है बल्कि आलू भी उच्च गुणवत्ता का मिलता है। जिसकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है। खुरपी या फावड़े से खुदाई करने पर बहुत–सा आलू कटकर खराब हो जाता है। मेंड़ के बीच में देशी हल चलाकर भी मिट्टी

से आलू निकाले जा सकते हैं। यदि खुदाई क्षेत्र अधिक है तो बैलचालित या ट्रैक्टरचालित यंत्रों द्वारा आलू खुदाई करनी चाहिए। इससे कम परिश्रम, समय व मजदूरी में बिना कटे आलू खोदे जा सकते हैं। आजकल आलू की खुदाई हेतु बहुत–सी आधुनिक मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं जिनमें पोटेटो कम्बाइन, पोटेटो डिगर एलीवेटर व मेकैनिकल डिगर प्रमुख हैं। इन मशीनों को 35 हार्सपॉवर के ट्रैक्टर द्वारा 2 कि.मी. प्रति घंटा की चाल से चलाया जाता है। यह मशीन आलुओं को मिट्टी से अलग कर जमीन पर बिखेर देती है। इससे खुदाई करने पर कटे या छिलका उतरे आलू की मात्रा न के बराबर मिलती है। आलू की खुदाई करने के बाद कंदों को सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखें। इसके लिए आलू के ढेरों को मिट्टी की हल्की परत या तिरपाल से ढककर रखे।

ग्रेडिंग – खुदाई उपरान्त आलुओं के छिलकों को पकाने के लिए 10–15 दिनों तक ठंडे और छायादार स्थानों पर एक मीटर ऊंचा ढेर बनाकर रख देना चाहिए। जिससे छिलके अच्छी तरह से पक जाएं। इसके बाद आलुओं की छंटाई कर उसे तीन श्रेणियों जैसे 30 ग्राम से छोटे, 30–80 ग्राम तक तथा 80 ग्राम से अधिक में बांटकर बोरियों में भरकर कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दें या प्रोसेसिंग यूनिट को बेच दें।

प्रसंस्करण – भविष्य में भारत को आलू में छिपे खजाने का भरपूर दोहन करना होगा। जिससे न केवल किसानों को अपनी फसल का आकर्षक मूल्य मिलेगा बल्कि भूमिहीन ग्रामीणों को रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। आलू के कई ऐसे पौष्टिक , स्वास्थ्यवर्धक व स्वादिष्ट उत्पाद बनाये जा सकते है जो वर्तमान परिवेश में लोगों के बदलते खानपान की आदतों व जीवनशैली के कारण उपभोक्ताओं के एक बड़े वर्ग को लुभा सकते हैं। इसके लिए सरकारी स्तर पर आलू के महत्व व उपयोगिता को बताने के लिए पर्याप्त प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। भारत में आलू का प्रसंस्करण मात्र एक प्रतिशत ही होता है। भारत में आलू का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। जैसे आलू को आटे के रूप में, आलू की चिप्स बनाकर, तले हुए आलू के रूप में, स्टार्च इत्यादि के रूप में आलू का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आलू से फ्रेंचफ्राई व लच्छा इत्यादि भी बनाए जा रहे हैं। प्रोसेसिंग के लिए इस समय अच्छी किस्मों में कुफरी ज्योति, कु. लवकार, कु. चंद्रमुखी, कु. चित्सोना–1, कु. चित्सोना–2, कु. चित्सोना–3, कु. सूर्या और कु. हिमसोना प्रमुख हैं। इन किस्मों में शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। कम शुगर होने के कारण इन किस्मों से बनाए चिप्सों का रंग काला नहीं होता है, वे सफेद ही बने रहते हैं। इन किस्मों को 10–12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लम्बे समय तक भण्डारित किया जा सकता है।

आलू भंडारण – उत्तर–पश्चिम भारत में आलू का अधिकांश उत्पादन फरवरी–मार्च माह के दौरान होता है। इस समय किसानों को बाजार में आलू का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः आलू को भंडारित करने की आवश्यकता पड़ती है। घरों के अन्दर या खेतों पर ढेरों में रखे आलुओं में खुदाई के दो माह बाद सूखने, अंकुरित होने व सड़ने की वजह से लगभग 15–20 प्रतिशत तक वजन में कमी आ जाती है। साथ ही आलू सिकुड़ने के कारण उचित मूल्य पर नहीं बिक पाता है। अतः उपरोक्त नुकसान से बचने के लिए शीतगृहों में आलू का भंडारण नितान्त आवश्यक है। ऐसा करने से आलू की पैदावार का एक बड़ा भाग सड़ने–गलने व सूखने से बचाया जा सकता है। परन्तु शीतगृहों की सीमित भंडारण क्षमता व उनके आसमान छूते किराए से बचने के लिए किसान भाई मार्च से मई के अन्त तक स्वस्थ व साफ–सुथरे आलू को बगीचों अथवा हवादार एवं छायायुक्त स्थानों पर 6 इंच मोटी पुआल/फूंस से अच्छी तरह ढेर को ढक कर रख सकते हैं। याद रहे ढेर की ऊंचाई एक मीटर व जमीन पर चौड़ाई तीन मीटर से अधिक न हो। इससे आलुओं में सिकुड़न नहीं होती तथा वजन में होने वाली कमी भी बहुत घट जाती है।

(लेखक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कार्यरत हैं।)
ई–मेलः –v.kumarnovod@yahoo.com

स्वास्थ्य-चर्चा

सेहत से भरपूर है बैंगन

साधना यादव

बैंगन में पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, थोड़ा-बहुत आयरन और विटामिन सी होता है। जो लोग वायु विकार के शिकार होते हैं, उन्हें बैंगन खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अर्थराइटिस के रोगियों को इस सब्जी के अलावा आलू-टमाटर से परहेज करना चाहिए। बैंगन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और खट्टी डकार भी दूर होती हैं। इसे हर सीजन में खाया जा सकता है, लेकिन सर्दी के सीजन में इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही लाजवाब होता है। त्वचा के लिए अति लाभदायक सब्जी बैंगन में ऐसे प्राकृतिक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में सहायक हैं। इतना ही नहीं, इस लाभकारी सब्जी में मौजूद पोटेशियम दिल को भी शक्ति प्रदान करता है जबकि बैंगन याददाश्त बढ़ाने के साथ ही स्नायु तंत्र को भी मजबूती देता है।

प्रकृति ने खाने की हर वस्तु में पोषक तत्वों के साथ ही औषधीय गुण भी शामिल किए हैं। ऐसी ही एक सब्जी है बैंगन। इसमें अन्य सब्जियों की तरह ही तमाम औषधीय गुण मौजूद हैं। हालांकि बैंगन की सब्जी खाने से कुछ लोग परहेज करते हैं, लेकिन इसमें पौष्टिकता कम नहीं है। इसी वजह से भारत के विभिन्न राज्यों में बैंगन को अलग–अलग तरीके से खाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में तो बैंगन प्रतिदिन किसी न किसी रूप में थाली में मौजूद रहता है। इस इलाके में बैंगन को सब्जी के अलावा चोखा के रूप में खाने का चलन खूब है।

बैंगन देखने में काफी आकर्षक होता है। भारत में बैंगन हर सीजन में उपलब्ध रहता है। इसकी ज्यादातर खेती उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में होती है। यहां तक कि इसे हर परिवार किसी न किसी रूप में प्रयोग करता है। यह सब्जी के साथ ही भरता, चोखा के रूप में सबसे ज्यादा खाया जाता है। वास्तव में भारत में यह आलू के बाद दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली

सब्जी है। विश्व में चीन 54 प्रतिशत पैदावार के साथ पहले स्थान पर है तो भारत 27 फीसदी पैदावार के साथ दूसरे स्थान पर। भारत में करीब 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बैंगन की खेती की जाती है। बैंगन की खेती हर सीजन में की जाती है। बैंगन गोल होने के साथ ही लंबे आकार का भी होता है। बैंगन का पौधा दो से तीन फुट ऊंचा खड़ा लगता है। फल बैंगनी या हरापन लिए हुए होता है। कुछ बैंगन का फल सफेद भी होता है।

बैंगन में पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, थोड़ा–बहुत आयरन और विटामिन सी होता है। आयुर्वेद के अनुसार आर्थराइटिस के रोगियों को इस सब्जी के अलावा आलू–टमाटर से परहेज करना चाहिए। बैंगन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और खट्टी डकारे भी दूर होती हैं। इसे हर सीजन में खाया जा सकता है, लेकिन सर्दी के सीजन में इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही लाजवाब होता है। ज्यों–ज्यों सर्दी जोर पकड़ती है बैंगन की खपत भी बढ़ती जाती है।

बैंगन भारत में वेदकाल से ही प्रचलित है। बैंगन दो रंगों में मिलता है– सफेद और बैंगनी। बैंगनी रंग की जाति अधिक गुण वाली मानी जाती है। बैंगन बड़े, मध्यम और छोटे आकार में मिलते हैं। मध्यम आकार वाला बैंगन अधिक गुणकारी माना जाता है। बड़ा बैंगन पित्तवर्धक होता है और पचने में भारी होता है। छोटा बैंगन पित्तनाशक है। सफेद बैंगन बवासीर के रोगियों के लिए विशेष हितकारी होता है। कोमल और बीजों वाला बैंगन अधिक गुणयुक्त और बलदायक होता है। गर्मियों में उगने वाले बैंगनों की अपेक्षा सर्दियों के मौसम में उगने वाले बैंगन अधिक स्वादिष्ट और गुणों से भरपूर होते हैं। बैंगन में कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन 'ए', बी–2, सी, लौह तत्व तथा कुछ क्षारों का समावेश होता है। यह याद रखें कि सब्जी बनाते समय इसका डंठल व्यर्थ समझकर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है। हां, इतना जरूर है कि अधिक दिनों तक रखे या सूखे हुए बैंगन पित्तकारक होते हैं। इसलिए इन्हें दो–तीन दिन से अधिक फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आग पर भुने हुए बैंगन पचने में बिल्कुल हल्के और पाचन शक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। यह अपच दूर करता है। मध्यम आकार के बैंगनों को सब्जी के रूप में उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये पित्तकारक नहीं होते। फिर भी बैंगन का अधिक प्रयोग पित्त प्रकृति वाले, अमल पित्त, अल्सर जैसे पित्त रोगियों को नहीं करना चाहिए। बैंगन को अधिक तेल में तलकर खाने से यह पचने में भारी हो जाता है। ताजा अनुसंधान से पता चला है कि बैंगन हमारे अमाशय को शक्ति देने के साथ–साथ भूख भी बढ़ाता है और इसे गैस और एसिडिटी के मरीज कब्ज खोलने वाली सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। त्वचा के लिए अति लाभदायक सब्जी बैंगन में ऐसे प्राकृतिक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने मे सहायक हैं। इतना ही नहीं, इस लाभकारी सब्जी में मौजूद पोटेशियम दिल को भी शक्ति प्रदान करता है जबकि बैंगन याददाश्त बढ़ाने के साथ ही स्नायु– तंत्र को भी मजबूती देता है।

बैंगन के औषधीय गुण

भूख बढ़ाने – बैंगन को कुछ लोग बादी मानते हैं, लेकिन यह मंदाग्नि यानी जिन्हें भूख नहीं लगती, उनके लिए फायदेमंद साबित होता है। बशर्ते बैंगन को आग पर सेंक कर गुड़ के साथ प्रयोग करना चाहिए। तेल में तला हुआ बैंगन ऐसे लोगों को नुकसान करता है।

पेट की गैस – पेट में गैस बन रही हो तो लहसुन और मेथी व हींग का चूर्ण डालकर बैंगन को पकाएं। इसकी सब्जी पेट की गैस को दूर करती है।

कब्ज – बैंगन और पालक को मिलाकर बनाया गया सूप कब्ज तोड़ता है। साथ ही पाचन शक्ति भी बढ़ाता है।

पथरी – पथरी के मरीजों के लिए बैंगन काफी फायदेमंद है। इसमें पथरी दूर करने के उत्तम गुण हैं। पेशाब की पथरी के रोगी को बैंगन का भरता खाना चाहिए।

मधुमेह – बैंगन मधुमेह के रोगियों के लिए कारगर है। इसका नियमित सेवन करने से मधुमेह नियंत्रित रहता है। धीरे–धीरे मधुमेह का असर भी कम होने लगता है।

पैरों में सूजन – पैरों में सूजन होने पर बैंगन को सेंककर लेप किया जा सकता है। इतना ही नहीं सेंके हुए बैंगन का भरता खाने से धीरे–धीरे पैरों की सूजन कम हो जाती है।

अनिद्रा – जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत हो, उन्हें खाने में बैंगन का प्रयोग करना चाहिए। शाम को शहद के साथ बैंगन की स्लाइस बनाकर लेने से अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है।

मलेरिया – मलेरिया के रोगियों के लिए बैंगन कारगर माना गया है। मलेरिया रोगी को सुबह खाली पेट चीनी के साथ नरम बैंगन काट कर कच्चा खाने को दिया जा सकता है।

कोलेस्ट्रॉल – बैंगन खाने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता–घटता नहीं है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। बैंगन के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर गिरता है। इस तरह के प्रभाव का प्रमुख कारण है बैंगन में पोटेशियम व मैगनीशियम की अधिकता। बैंगन की पत्तियों के रस का सेवन करने से भी रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम किया जा सकता है।

मस्तिष्क के लिए उपयोगी – बैंगन में पाए जाने वाले तत्व मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को रोकने में कारगर होते हैं। इससे जहां दिमागी बीमारियां नजदीक नहीं फटकती हैं वहीं दिमाग तेज रहता है। इसके पौधे में जो न्यूट्रियन्ट्स पाए जाते हैं वह हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। यह किसी भी प्रकार के नुकसान से हमारी कोशिका की झिल्ली को बचाते हैं। यह दिमाग को फ्री रैडिकल से बचाता है और ब्रेन का विकास करता है।

दिल का दौरा – बैंगन में मौजूद लौह तत्व दिल का दौरा रोकते हैं। ऐसी स्थिति में हार्ट के मरीजों को भी बैंगन का सेवन करना चाहिए। बैंगन हृदय रोग और स्ट्रोक की संभावना को कम करता है।

कैंसर – बैंगन पाचन–तंत्र को मजबूत बनाता है। फाइबर की वजह से कब्ज से बचाता है। यह एंटी आक्सीडेंट से भी भरपूर है। ऐसे में कैंसर का खतरा खत्म हो जाता है। अगर आप हर रोज बैंगन खाएंगे तो आपका शरीर कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएगा। यह खासकर पेट के कैंसर से लड़ने में सहायक है।

एंटी बैक्टीरियल गुण – बैंगन में मौजूद तत्व वायरल और बैक्टीरियल विरोधी हैं। विटामिन सी की वजह से इसके एंटी बैक्टीरियल गुणों को बेहतर माना गया है।

चेहरे की कांति – बैंगन खनिज, विटामिन और आहार फाइबर का अच्छा स्रोत है। इस वजह से इसे खाने से चेहरे की कांति लौटती है।

त्वचा की चमक – बैंगन में मौजूद खनिज एवं विटामिन त्वचा रोग में कारगर साबित होते हैं। त्वचा की चमक बनाए रखने में भी मदद करते हैं।

बालों का रुखापन – बैंगन में पानी की भरपूर मात्रा है। इसके अलावा अन्य खनिज तत्व बालों की चमक लौटाते हैं। बालों के झड़ने की समस्या का समाधान देते हैं। बैंगन सिर को पोषण देता है। इसके खनिज और विटामिन बालों में खुश्की सहित अन्य समस्याओं को दूर करते हैं। बालों को बढ़ने में भी मददगार साबित होते हैं।

संक्रमण – बैंगन में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है जो प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है और शरीर को संक्रमण से मुक्त रखने में मदद करता है।

दांत दर्द – बैंगन का रस दांत के दर्द में लाभदायक प्रभाव दिखलाता है। अस्थमा के उपचार के लिए बैंगन की जड़ें प्रयुक्त की जाती हैं।

रक्त अल्पता – बैंगन को रक्त अल्पता दूर करने में भी सहायक माना जाता है। भुने हुए बैंगन में थोड़ी–सी शक्कर डालकर सुबह खाली पेट खाने की सलाह देते हैं, मानना है कि ऐसा करने से शरीर में रक्त की कमी दूर हो जाती है।

लीवर रोग – लीवर की बीमारियां होने पर भी बैंगन का सेवन लाभदायक प्रभाव दिखलाता है। यही वजह है कई दवाईयां बनाने में इसकी पत्तियां आधारभूत तत्व की तरह कार्य करती हैं।

सिगरेट छुड़ाए – प्राकृतिक तरीके से सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो डाइट में बैंगन का सेवन अधिक करें। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तहत इसमें मौजूद निकोटिन की सीमित मात्रा सिगरेट छोड़ने वाले लोगों के लिए मददगार हो सकती है।

बैंगन खाने में सावधानियां

बैंगन जहां खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही विभिन्न बीमारियों को दूर करने में सहायक है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक गुण भी हैं। ऐसी स्थिति में बैंगन अत्यधिक पित्त रोगियों को नहीं दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिला को भी इसका उपयोग कम करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है।

रसोई में बैंगन

बैंगन को अलग–अलग रूपों में खाया जाता है। कुछ लोग इसकी सब्जी खाते हैं तो कुछ लोग चोखा एवं करी सहित अन्य व्यंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। बैंगन के पकौड़े का स्वाद भी लजीज होता है। यही वजह है कि आलू की तरह ही बैंगन हर किचन की शान है। इसके जरिए आप किचन को चमका सकते हैं। यानी जब कोई भी सब्जी न हो तो बैंगन के सहारे अलग–अलग स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। बैंगन की सब्जी बनाने में कोई अतिरिक्त व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप दूसरी सब्जियां बनाते हैं, उसी तरह से बैंगन आलू की सब्जी भी तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे मसालेदार बनाए अथवा सादी। इसे तरीयुक्त बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं और सूखी भुजिया के रूप में बनाना चाहे तो भी। कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेश है संक्षिप्त में विभिन्न व्यंजन बनाने के तरीके:

बैंगन की करी

बैंगन करी स्वाद में लाजवाब बनती है। यदि आप 500 ग्राम बैंगन की करी तैयार कर रही हैं तो इसके लिए चार कप दही, दो चम्मच बेसन, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला, तलने के लिए तेल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा करी के लिए चार टमाटर, एक हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक, दो चम्मच छिले मूंगफली के दाने, आधा कप दही, दो चम्मच तेल, चुटकीभर हींग, आधा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला। दो चम्मच हरा धनिया की जरूरत पड़ेगी। इसे तैयार करने के लिए पहले बैंगन को छील लें। फिर एक कटोरी में फेंटी हुई दही, गरम मसाला और बेसन डाल कर मिला लें। बैंगन को चोकोर टुकड़े में काट लें। फिर इसमें मसाले तैयार करके 15 मिनट रख दें। इसके बाद एक कड़ाही में तेल गरम करके बैंगन के टुकड़े डाले। तलने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद तरी तैयार करें।

तरी तैयार करने के लिए

टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, मिर्च आदि को धोकर काट लें। मूंगफली के दानों को भी मिक्सी में डाल लें और इन्हें पीस कर बारीक पेस्ट बना लें। कड़ाही में तेल गरम करके धीमी आंच में हींग, जीरा भूने। फिर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल कर टमाटर–मूंगफली वाला पिसा मसाला डाल लें। लाल मिर्च डाल कर इसे तेल छोड़ने तक भूनें। जब तेल मसाले के ऊपर तैरने लगे तो इसमें फैंटी हुई दही डाल कर मिला लें। चम्मच से चलाते हुए इसे फिर से तेल छोड़ने तक भूनें। जब मसाला भुन जाए तो इसमें तले हुए बैंगन के टुकडे डाल कर मिला लें। तरी में एक अथवा आधा कप पानी डालें। फिर उबाल आने तक चलाते हुए पकाएं। सब्जी में गरम मसाला डाल कर मिला दें। इसे ढक कर 5–6 मिनट तक पकने दें। पकने के बाद ऊपर से हरा धनिया डाल दें।

बैंगन का चोखा

यह बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध डिश है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पारंपरिक तौर पर लिट्टी को आटे की लोई में सत्तू की भरावन भरकर बनाया जाता है, लेकिन चोखा आलू व बैंगन का लाजवाब होता है। इसे तैयार करने के लिए दो बैंगन,. दो टमाटर, दो प्याज, दो हरी मिर्च, चार–पांच लहसुन कली, दो चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा, दो चम्मच सरसों तेल, एक इंच लहसुन टुकड़ा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच हरा धनिया कटा हुआ एवं स्वादानुसार नमक की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए पहले सभी कच्चा सामान धोकर सुखा लें। फिर बैंगन, टमाटर व आलू को कंडे, तंदूर आदि पर सेंक कर पका लें। भुनने के बाद इसे छिल लें। अब टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को भी गैस पर हल्का–सा भुनकर टमाटर, लहसुन और प्याज को छिलके हटाकर बारीक काट लें और भुनी हुई हरी मिर्च को भी बारीक काट लें। अब एक कड़ाही में सरसों का तेल डालकर गरम करने के लिए गैस पर रखें। जब तेल हल्का–सा गरम हो जाए तब हींग और जीरा डालकर हल्का–सा भुन लें और अब इसमें कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डालकर लगभग 2 मिनट के लिए भुन लें। इसके बाद इस मसाले में मैश किया हुआ बैंगन और कटे हुए टमाटर को डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इस बैंगन के चोखे में नमक, धनियां पाउडर को डालकर अच्छी तरह मिला लें। आप चाहें तो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को भुनने के बजाय कच्चा भी मिला सकते हैं। स्वाद लाजवाब रहेगा।

100 ग्राम बैंगन में मौजूद पोषक तत्व

कुल कार्बोहाइड्रेट	17.8ग्राम
प्रोटीन	8ग्राम
वसा	5.2ग्राम
फाइबर	4.9ग्राम
फैट	27.5ग्राम
कोलेस्ट्रॉल	16मिलीग्राम
शूगर	11.4ग्राम
आयरन	6मिलीग्राम
विटामिन–ए	6.4मिलीग्राम
कैल्शियम	525मिलीग्राम
सोडियम	62मिलीग्राम
पोटेशियम	618मिलीग्राम

(लेखिका किसान क्लब की सदस्य हैं।)
ई–मेलः skynpr@gmail.com

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

In Association with

ETEN IAS
Institute for Administrative Services

ALS IAS

India's largest IAS Coaching Network

UPSC CIVIL SERVICES EXAM 2014 -15

INTEGRATED FOUNDATION COURSE:

Prelims Cum Mains • Optionals • Interview Guidance
• Current Affairs • All India Mock Test Series

(English & हिन्दी माध्यम)

BATCH STARTING JUNE & JULY'14

INDIA'S BEST IAS MENTORS

MR. JOJO MATHEWS

MR. MANISH GAUTAM

MR. SHASHANK ATOM

MR. MANOJ K. SINGH

Our Publications

www.pearson.co.in

1464 RANKS IN LAST 12 YEARS

161 successful candidates in 2013

ALOK RANJAN JHA	S. NAGARAJAN	RUKMANI RIAR	ANUPAMA T V
ALL INDIA RANK 1	ALL INDIA RANK 1	ALL INDIA RANK 2	ALL INDIA RANK 4
2001 Exam	2004 Exam	2011 Exam	2009 Exam

Call: 9654200517/23 I Toll free: 1800-1038-362
Email: csp@etenias.com I Website: www.etenias.com

ETEN IAS CENTRES: Bangalore, Bhopal, Bilaspur, Chandigarh, Chennai(Anna Nagar & Adyar), Cochin(Ernakulam), Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jamshedpur, Kanpur, Kolkatta, Lucknow, Patna, Patiala, Raipur, Trivendram

ALWAYS LEARNING

PEARSON

KH-126/2014

बदल रहीं हैं रूढ़िवादी प्रथाओं को स्वयंसहायता समूहों की महिलाएं

रामचरण धाकड़

राजस्थान के लुपिन महिला स्वयंसहायता समूह ने न केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए नई पहल की है बल्कि कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक अलग ही अंदाज में काम कर रहा है। महिला स्वयंसहायता समूह की सदस्य महिलाओं को छोटे परिवार का महत्व समझ में आने लगा है। साथ ही समूह में शिक्षा के प्रति भी जागृति आई है। समूह की सदस्य महिलाएं अपने बालकों के साथ-साथ बालिकाओं को भी उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास कर रही हैं।

राजस्थान के भरतपुर जिले के धर्मपुरा गांव में लुपिन महिला स्वयंसहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती रामकटोरी की पुत्री संतो देवी के शादी समारोह में अलग ही नजारा दिखाई दे रहा था जहां समूह की सदस्य महिलाएं शादी समारोह का सारा कार्य संभाले हुई थीं वहीं संतो देवी को कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने के लिए सात फेरों के स्थान पर आठ फेरे दिलाए गए अर्थात् आठवां फेरा उसको कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ के रूप दिलाया गया था। उसे इस बात की भी शपथ दिलाई गयी कि प्रथम प्रसव में बेटी का जन्म होता है तो भी उसे कन्या भ्रूण हत्या जैसे कदम नहीं उठाने है। इसी तरह जाटौली रथभान गांव में सुनीता की बेटी सुमन और भरतपुर शहर की राजरानी की बेटी पिंकी को भी आठ फेरे दिलाए गए।

कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की दूसरी पहल बहताना, चैनपुरा, खेरिया पुरोहित सहित आसपास के गांवों में देखी जा सकती है। समूह की जिस सदस्य महिला के यहां बेटी का जन्म होता है वहां खुशी मनाई जाती है और बेटी के नाम पर एक पौधा पीपल, तुलसी, जामुन, नीम आदि का लगाया जाता है। यहां तक कि बेटी का नाम तुलसी, नर्मदा, गंगा, यमुना जैसी धार्मिक व प्राकृतिक सम्पदाओं के नाम पर रखा जाता है।

महिला स्वयंसहायता समूह की सदस्य महिलाओं को छोटे परिवार का महत्व समझ आने लगा है। समूह की जिन सदस्य महिलाओं के दो बच्चे होते हैं उसे परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबंदी कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है चाहे उसके दोनों बच्चे बेटियां ही क्यों न हो। रामपुरा गांव की स्वयं–सहायता समूह की सदस्य महिला अंगूरी और उसके पति को समझाकर नसबंदी कराने के लिए तैयार किया और एक सप्ताह बाद ही सरकारी चिकित्सालय ले जाकर अंगूरी की नसबंदी करा दी। इसके अलावा ऐसी सदस्य महिलाएं जो बच्चे पैदा कर सकती

हैं उन्हें दो बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए परिवार कल्याण के साधन अपनाने की सलाह भी दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बने महिला स्वयंसहायता समूहों के गठन, सामूहिक रूप से स्वरोजगार के कार्यों के संचालन, समूहों की होने वाली नियमित बैठकों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों, रूढ़िवादी प्रथाओं के उन्मूलन की चर्चा के कारण आपसी भेदभाव कम हुआ है और विपत्ति के समय जाति प्रथा अथवा ऊंच–नीच की भावना को छोड़कर संगठित होकर सामना करती हैं। भरतपुर जिले के वैर पंचायत समिति क्षेत्र के मजाजपुर गांव में 3 गरीब परिवारों के घरों में लगी आग में सारा घरेलू सामान आग की भेंट चढ़ गया। यहां तक कि उनके पास खाने और ओढ़ने–पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे। ऐसी प्राकृतिक आपदा में गांव की महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं ने घर–घर जाकर खाने के लिए गेहूं व पहनने के लिए कपड़े एकत्रित कर पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराए। यही स्थिति नगला हरचंद गांव में गरीब महिला की बेटी की शादी में देखने को मिली जहां शादी के लिए बर्तन, कपड़े, खाने–पीने का सारा सामान सदस्य महिलाओं ने एकत्रित कर उपलब्ध कराया।

महिला स्वयंसहायता समूहों की सबसे बड़ी जाग्रति शिक्षा के प्रति आई है। समूह की सदस्य महिलाए अपने बालकों के साथ बालिकाओं को भी उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। भयौराना गांव की समूह की सदस्य महिला मुकेश जादौन अपनी पुत्री को चार्टर्ड एकाउंटेंट, धर्मपुरा की श्रीमती संतो अपनी दो पुत्रियों को नर्सिंग, खरेरा गांव की ज्ञानवती अपनी पुत्री को बी.टेक., नगला करनसिंह की समूह की सदस्य कलावती अपनी दो बेटियों को उच्च शिक्षा दिला रही है। इसी प्रकार सेवर पंचायत समिति क्षेत्र के नौह गांव की स्वयंसहायता समूह की अध्यक्ष जयदेई ने बकरीपालन के लिए ऋण लेकर काम शुरू किया और बचत राशि से समय पर लिए गए ऋण की किस्तें लौटाई तथा अपने पुत्र को चिकित्सक की शिक्षा दिलाई जो महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए उदाहरण बन गया है। समूह की महिलाओं में शिक्षा के प्रति तो ऐसी जाग्रति आई है कि सभी बालक–बालिकाओं को नियमित स्कूल भेज रही हैं। इसके अलावा परिवार के स्वास्थ्य, टीकाकरण, साफ–सफाई के प्रति भी समूह की महिलाएं जाग्रत हुई हैं। जिन सदस्य महिलाओं के बालक–बालिकाओं का समय पर टीकाकरण नहीं हुआ उन्हें प्रोत्साहित कर टीकाकरण कराया जा रहा है।

गांवों में साफ–सफाई के प्रति ऐसी जाग्रति आई है कि सदस्य महिलाओं ने साफ–सफाई का अभियान भी चलाया। धर्मपुरा गांव की महिलाए गांव में साफ–सफाई के लिए प्रतिदिन अपने घर के आसपास व मुख्य सड़क मार्ग की सफाई करती है। गांव की विशेष पहचान कायम करने के लिए जब पूरे गांव के मुख्य मार्ग के मकानों पर गुलाबी रंग किया गया तो समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इस कार्य में भागीदारी निभाई जिसका परिणाम रहा कि धर्मपुरा को आज ''पिंक विलेज'' के नाम से पहचाने जाने लगा है।

स्वयंसहायता समूह की महिलाओं में सामाजिक कुरीतियों को रोकने के साथ ही मृत्युभोज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए भी जाग्रति आई है और उन्होंने आगे बढ़कर मृत्युभोज पर व्यय होने वाली राशि को विकास के कार्यों में खर्च किया है। डीग पंचायत समिति क्षेत्र के वहज गांव की महिला बलवीरी के पति जसवन्त की मृत्यु होने पर उसने मृत्युभोज के स्थान पर जमीन दान देकर सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। इस सामुदायिक भवन का पूरे गांव द्वारा सामाजिक कार्यों में उपयोग किया जा रहा है।

गठित किए दो हजार से अधिक समूहों को स्वरोजगार कार्यों से जोड़ा

लुपिन ने भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे सर्वांगीण विकास के दौरान पाया कि गांव की अधिकांश महिलाओं को घरेलू कामकाज के बाद अन्य कोई काम नहीं रहता और गरीब

अथवा भूमिहीन परिवारों की महिलाओं को पूरे वर्ष कृषि मजदूरी नहीं मिलने से उनका परिवार आर्थिक समस्याओं से परेशान रहता था। इस दृष्टि से संस्था ने विशेष रूप से गरीब वर्ग की महिलाओं के 2 हजार 870 स्वयंसहायता समूह बनाए जिन्हें स्थानीय आवश्यकता के आधार पर स्वरोजगार कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया और राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों से आसान शर्तों पर लगभग 10 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया कराया।

इस ऋण राशि से स्वयंसहायता समूह की महिलाओं ने ऐसे स्वरोजगार के समूहों अथवा एकल रूप में कार्य शुरू किए जिनके लिए कच्चा माल स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सके और तैयार माल की स्थानीय बाजार में बिक्री हो सके। समूह की महिलाए पायल निर्माण, चैन झलाई, तुलसीमाला निर्माण, रेडीमेड गारमेंट निर्माण, मुर्गीपालन, बकरीपालन, दूध के विभिन्न उत्पाद तैयार करने, सब्जी विक्रय, फूलों की खेती, सिलाई–कढ़ाई, आरी–तारी, परचून की दुकान, आटा चक्की संचालन, ब्यूटीपार्लर जैसे कार्य कर रही हैं। इसके अलावा कुम्हेर पंचायत समिति क्षेत्र में 27 महिला स्वयंसहायता समूहों ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पोषाहार बनाकर उपलब्ध कराना शुरू किया है जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। समूह की महिलाओं द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण को समय पर वापिस किया है और बचत राशि परिवार के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। मुख्य रूप से तो स्वयंसहायता समूह की महिलाओं के परिवारों के बालक–बालिकाओं ने उच्च शिक्षा लेना प्रारम्भ किया है।

स्वयंसहायता समूह की महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से लुपिन संस्था ने दूरदराज की लगभग 900 महिलाओं के स्वास्थ्य रक्षा कार्ड बनाए हैं। इन कार्डों के द्वारा महिलाएं अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करा रहीं हैं। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से समूह की सभी महिलाओं का बीमा कराया गया है जिसमें दुर्घटना, झोंपड़ी बीमा व राजराजे वरी बीमा आदि शामिल हैं।

भरतपुर जिले में सेवर पंचायत समिति 167, रूपवास में 170, डीग में 148, कामां में 138, नदबई में 98, नगर में 33, बयाना में 125, वैर में 149 और कुम्हेर पंचायत समिति क्षेत्र में 1640 समूहों का गठन किया गया है। इन समूह की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ ही संस्था ने इन्हें देश की प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं और प्रमुख शहरों के बाजारों का भी अवलोकन कराया है ताकि वे अपने उत्पादों में सुधार लाकर इन बाजारों में बेच सकें। संस्था ने समूह की महिलाओं को दिल्ली हाट बाजार, केन्द्रीय पशु अनुसंधान केन्द्र, गुजरात के लिज्जत पापड़ उद्योग समूह सहित अन्य क्षेत्रों का भी भ्रमण कराया जिसका परिणाम रहा कि समूह की कुछ महिलाओं ने अपने उत्पादों में सुधार लाकर इन्हें बड़े बाजारों में विक्रय करना शुरू किया है। दिल्ली हाट में भरतपुर जिले की महिलाए रेडीमेड गारमेंट, तुलसीमाला, मार्बल के सजावटी आइटम विक्रय करने ले जा रही हैं।

स्वावलम्बी महिलाओं का परिवार में बढ़ा सम्मान

लुपिन फाउण्डेशन द्वारा गठित किए गए महिला स्वयंसहायता समूहों को विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराया जाता है और रोजगार संचालन के लिए समय–समय पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है जिसका परिणाम रहा कि महिलाएं अपना रोजगार का कार्य कर परिवार की आय में भागीदार बन रही हैं। यही कारण है कि महिलाओं का परिवार में सम्मान बढ़ा है।

अब तक परिवार के सामाजिक अथवा अन्य कार्यों के निर्णय लेने में पुरुषों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती आयी है लेकिन स्वयंसहायता समूह की स्वरोजगार करने वाली महिलाऐं परिवार की आर्थिक आय में भागीदार बनने के कारण उन्हें परिवार के निर्णयों में शामिल किया जा रहा है जिससे महिलाओं का परिवार में जहां एक ओर सम्मान बढ़ा है वहीं दूसरी ओर उनकी पहचान भी कायम हुई है। नदबई पंचायत समिति क्षेत्र के गादौली गांव के स्वयंसहायता समूह की श्रीमती विमला अपना पशुपालन का कार्य कर प्रतिदिन करीब 100 से 125 रुपये आसानी से कमा रही

है। श्रीमती विमला ने स्वयंसहायता समूह के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक से 30 हजार रुपये का ऋण लिया और भैंस खरीद कर दुग्ध विक्रय का कार्य शुरू किया। भैंस के चारे पानी की व्यवस्था वह स्वयं करने लगी और आय में से बैंक को नियमित किश्त का भुगतान करने लगी जिससे मात्र एक वर्ष में ही उसका ऋण पूरा हो गया। उसके बाद मिली आय बच्चों की शिक्षा व परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में व्यय की जाने लगी और अब तीन साल बाद तो उसका परिवार गरीबी से मुक्त होकर खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

सेवर पंचायत समिति के बझेरा गांव में महिला स्वयंसहायता समूह की महिलाओं ने सामूहिक रूप से सब्जी की खेती शुरू की जिससे उनमें विश्वास की भावना कायम हुई। गांव में जब सार्वजनिक स्थान पर शराब का ठेका खोला गया तो उसके विरोध में स्वयंसहायता समूह की महिलाएं आगे आयीं और बाद में सार्वजनिक पंचायत में किए गए फैसले में समूह की महिलाओं के निर्णय को अंतिम माना गया। यही स्थिति वैर पंचायत समिति क्षेत्र के नगला सिरसियान गांव के स्वयंसहायता समूह की रही जहां गांव के सार्वजनिक रास्ते पर हुए अतिक्रमण के विरोध में महिलाओं ने तहसीलदार के कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया जिस पर तहसीलदार ने तत्काल अतिक्रमणों को हटवाकर रास्ते को आवागमन के लिए चालू कराया।

पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्रों में प्रवेश

स्वयंसहायता समूह की महिलाओं को मिली प्रेरणा, मार्गदर्शन से आए आत्मविश्वास से ऐसे स्वरोजगार के कार्य भी शुरू किए हैं जिन पर पुरुषों का एकाधिकार रहा है। डीग पंचायत समिति क्षेत्र के सिनसिनी गांव के महिला स्वयंसहायता समूह की सदस्य श्रीमती रामवती ने वैल्डिंग का कार्य शुरू किया। अपने पति से वैल्डिंग का कार्य सीखकर स्वयं लौटे की जालियां, गेट, रेलिंग आदि बनाकर परिवार की आय में भागीदार बनी हैं। इसी प्रकार नगला करनसिंह की श्रीमती केशवती आटा चक्की संचालन करने, खरैरी एवं बागरैन गांवों में महिला स्वयंसहायता समूह पान की खेती करने, नगला हरचंद गांव में समूह की महिलाएं मुर्गीपालन करने, पहाड़ी में समूह की महिलाएं मार्बल हैण्डीक्राफ्ट तैयार करने, नगला धाकड़ गांव में चैन झलाई करने जैसे कार्य में जुटी हुई है।

आयोजित किए जाते हैं स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण

महिला स्वयंसहायता समूह की सदस्य महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण से पहले समूह की सदस्य महिलाओं की बैठकें आयोजित होती हैं जिसमें प्रशिक्षण की उपयोगिता एवं कच्चे माल की उपलब्धता और उसके विक्रय आदि के बारे में विस्तार से विचार–विमर्श किया जाता है ताकि स्वरोजगारपरक कार्य आसानी से संचालित हो सके। प्रशिक्षण पर होने वाली व्यय राशि लुपिन फाउण्डेशन द्वारा वहन की जाती है। प्रशिक्षण के लिए देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से भी सम्पर्क किया जाता है ताकि आधुनिकतम तकनीक का उपयोग किया जा सके।

भरतपुर जिले का भू–भाग जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल के नजदीक है वहां पूजा–पाठ एवं धार्मिक महत्व की सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उत्पादित सामग्री की आसानी से बिक्री हो सके। संस्था ने तुलसीमाला बनाने का काम शुरू किया है जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं। भरतपुर जिले की स्वयंसहायता समूह द्वारा तैयार की गई विभिन्न डिजाइनों की तुलसीमाला उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के अलावा देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी विक्रय के लिए भेजी जा रही हैं। इसी प्रकार नदबई तहसील में बनायी जाने वाली चमड़े की जूतियों पर नक्काशी का कार्य भी स्वयंसहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इन जूतियों की मांग देश के बाहर भी निरन्तर बढ़ रही है।

भरतपुर जिले में महिला स्वयंसहायता समूह की महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण और कार्यों की अद्यतन जानकारी रखने के लिए महिला सुपरवाइजरों को पीसी टेबलेट उपलब्ध कराए हैं। संस्था स्वयंसहायता समूह की महिलाओं के कार्यों का निरंतर पर्यवेक्षण कर रही है ताकि समूह की महिलाओं को स्वरोजगार संचालन में आने वाली समस्याओं का समय पर निराकरण किया जा सके।

(लेखक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भरतपुर में कार्यरत हैं।)
ई–मेलः redhakar@gmail.com

हमारे आगामी अंक

सितंबर, 2014 – **गांवों से पलायन का बदलता परिदृश्य** (Rural Migration)

अक्टूबर, 2014 – **गांवों में रोजगार (विशेषांक)** (Rural Employment (Special Issue)

नवंबर, 2014 – **कृषि वित्त प्रबंधन** (Agricultural Financing)

दिसंबर, 2014 – **कृषि का व्यवसायीकरण** (Commercialisation of Agriculture)

जनवरी, 2015 – **ग्रामीण–शहरी लिंकेज** (Rural-Urban Linkages)